सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 209, नई दिल्ली । मंगलवार, 08 अक्टूबर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा।

03 इस रामलीला ने बनाया रिकॉर्ड, 41 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा

06 सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की चुनौतियां

08 आदिशक्ति की आराधना में आधुनिकता का तड़का मत लगाओ।

दिल्ली के परिवहन आयुक्त दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के खिलाफ़ हैं, आखिर क्यों?

संजय बाटला

नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं दिल्ली में ना तो ठंड शुरु हुई और ना ही अभी तक किसी राज्य में पराली जलनी शुरु हुई है फिर भी सम्पूर्ण दिल्ली की वायु गुणवता बुरी तरह बिगड़ चुकी हैं आखिर क्यों ओर किस कारण से नही हो पा रहा प्रदूषण का समाधान?

असलियत यह है की दिल्ली सरकार, वायु गुणवता आयोग और दिल्ली परिवहन विभाग नहीं चाहते हैं की दिल्ली प्रदुषण मुक्त हो यानी दिल्ली की वायु गुणवता सही रहे।

इसका कारण जनता को जानना जरूरी है क्योंकि प्रदूषण / वायु गुणवता के बिगड़ने से दिल्ली सरकार के राजस्व में इतना पैसा जनता से चालान और जुर्माने से आ रहा हैं जितना किसी भी रूप में कही से भी एकत्र नही हो सकता।

परिवहन विभाग हर सम्भव तरीके से राजस्व में इजाफा करने का पिछले कई सालों से कार्य कर रहा है यह सर्व विदित है।

नए वाहनों के पंजीकरण होने से राज्य की पास पार्किंग और रोड टैक्स के नाम पर बड़ा मोटा राजस्व आ जाता है। ऊपर से परिवहन विभाग द्वारा चालान जिनकी कोई सीमा नहीं से भी बिना किसी सीमा से राजस्व आता है।

पिछले एक महीने से बिना किसी पूर्व सूचना दिए दिल्ली में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा अपनी सियासत और हठधर्मी के तहत घोषित माफ किए हुए रोड टैक्स को जबरन जुर्माने सहित राजस्व में इजाफा कराने के उद्देश्य से मालिकों को भरने के लिए मजबूर कर रहा है जिस कारण वाहन मालिकों द्वारा अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को खड़ा करवा रखा है।

अगर इलेक्ट्रिक वाहनों के चलने से दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में आ सकता है तो क्यों परिवहन विभाग ने गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाकर दिल्ली में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को खड़ा करने के लिए वाहन मालिकों को मजबूर किया हुआ है, बड़ा सवाल?

व्यवसायिक गतिविधियों में खास तौर पर सार्वजनिक सवारी सेवा में इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली में पंजीकृत ना हो पाए इसके लिए असेवधानिक तर्क का प्रयोग कर दिल्ली परिवहन विभाग के विशेष परिवहन आयुक्त और आयुक्त पंजीकरण रोकने का प्रयास करते आ रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इन्हे व्यवसायिक गतिविधियों में अधिकतम पंजीकृत करवाने के उद्देश्य को लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों को परमिट की जरूरत से मुक्त किया हुआ है पर दिल्ली के विशेष परिवहन आयुक्त और आयुक्त परमिट के नाम से इनका पंजीकरण रोकने में लिप्त हैं।

अर्थात यह साफ सिद्ध होता है की दिल्ली परिवहन विभाग में आसीन आयुक्त और विशेष परिवहन आयुक्त दिल्ली को प्रदुषण मुक्त कराने के लिए नही अपितु प्रदूषण के नाम से जनता से खरबों रुपए वसूल कर राजस्व में इजाफा करने में सलग्न है।

दूसरी तरफ दिल्ली सरकार सड़को को गड्ढा मुक्त, जाम मुक्त ना करवाकर और सड़को पर सफाई व्यवस्था ना करवाकर दिल्ली की वायु गुणवता को स्वयं खराब करवा कर दिल्ली की जनता से बिना गिनती का राजस्व वसुलने का रास्ता बनवा कर विभागों को दे रही है।

तीसरी तरफ वायु गुणवता आयोग वायु गुणवता बिगड़ने का सही कारण जानते हुए भी उसके प्रति सख्ती बरतने की जगह जनता पर पाबंदी लगा कर परिवहन एवम्-अन्य विभागों को जनता से खुली लूट का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

जब आयोग, सरकार ओर सरकारी विभाग ही प्रदूषण नियंत्रण नहीं होने देगें तो प्रदूषण मुक्त दिल्ली बन ही कैसे सकती हैं, बड़ा सवाल?

येलो लाइन पर सफर करने वाले ध्यान दें! देरी से चल रही मेट्रो, स्कूल-ऑफिस जाने वाले हो रहे

दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर ट्रेन देरी से चल रही है। इससे सुबह समय से स्कूल-कॉलेज और दफ्तर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। येलो लाइन पर हैदरपुर बादली मोड़ और जहांगीरपुरी के बीच ट्रेन सेवाओं में देरी हो रही है। इसके अलावा अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य हैं। डीएमआरसी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो के सबसे कॉरिडोर येलो लाइन (समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम) पर सोमवार सुबह एक घंटे से मेट्रो का परिचालन प्रभावित है। इस वजह से व्यस्त समय में यात्रियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने अभी तक परिचालन प्रभावित होने का कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन राहत की बात है कि हैदरपुर बादली से जहांगीरपुरी के बीच येलो लाइन के छोटे से हिस्से पर ही परिचालन प्रभावित है।

येलो लाइन की मेट्रो में सबसे अधिक सफर करते हैं यात्री

येलो लाइन के बाकी हिस्से पर परिचालन सामान्य है। डीएमआरसी ने सुबह 8:50 बजे एक्स पर पोस्ट कर यात्रियों को इसकी सूचना दी है और कहा है कि हैदरपुर बादली से जहांगीरपुरी के बीच मेट्रो परिचालन प्रभावित है। येलो लाइन की मेट्रो में सबसे अधिक यात्री सफर करते हैं। इस वजह से येलो लाइन की मेट्रो में प्रतिदिन पैसेंजर जर्नी करीब 18-20 लाख होती है।

इस वजह से येलो लाइन की मेट्रो ट्रेन में यात्रियों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। सुबह में समयपुर बादली और जहांगीरपुरी से भी नौकरी पेशेवर बहुत लोग मेट्रो से गुरुग्राम जाते हैं। उन्हें सफर में परेशानी का सामना करना पड़ा। डीएमआरसी ने अपने पोस्ट में भी परिचालन प्रभावित होने का कारण स्पष्ट नहीं किया है।

येलो लाइन पर कल भी परिचालन रहा प्रभावित

इससे पहले, कल रविवार को भी सुबह येलो लाइन (समयपुर बादली-मिलेनियम सिटी गुरुग्राम) पर मेट्रो परिचालन करीब एक घंटे तक प्रभावित रहा। सुबह करीब पौने सात बजे के बाद इस कॉरिडोर पर मेट्रो सामान्य हुई। इस दौरान 10 मिनट के अंतराल पर मेट्रो मिली। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन की मरम्मत के चलते ऐसा सेवाएं प्रभावित रही।

दो मेट्रो स्टेशन रहे बंद

विश्वविद्यालय से कश्मीरी गेट स्टेशन के बीच सुबह 6:40 बजे तक मेट्रो का परिचालन बंद रहा। विधानसभा और सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन बंद रहे। विश्वविद्यालय से मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के लिए पहली मेट्रो सुबह 6:45 बजे उपलब्ध हुई।

वहीं, कश्मीरी गेट से समयपुर बादली के लिए पहली मेट्रो सुबह 6:52 बजे उपलब्ध हुई। समयपुर बादली से विश्वविद्यालय और कश्मीरी गेट से मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के बीच परिचालन सामान्य रहा।

सिग्नल सिस्टम के केबल पर चोरों की नजर

एक हरकत से मेट्रो रही प्रभावित; लाखों यात्री हुए परेशान

दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर हैदरपुर बादली मोड से जहांगीरपुरी के बीच सिग्नल सिस्टम के केबल चोरी की कोशिश की गई। इससे सिग्नल केबल क्षतिग्रस्त हो गया और येलो लाइन पर मेट्रो का परिचालन धीमा हो गया। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में ज्यादा समय लगा। प्रभावित हिस्से पर धीमी गति से परिचालन जारी रखा गया है और रात में केबल को ठीक किया जाएगा।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो के सबसे व्यस्त कॉरिडोर येलो लाइन (समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम) पर हैदरपुर बादली मोड से जहांगीरपुरी के बीच शरारती तत्वों ने सिग्नल सिस्टम का केबल चोरी करने का प्रयास किया। इस वजह से सिग्नल का केबल क्षतिग्रस्त हो गया।

इससे सोमवार को येलो लाइन पर हैदरपुर बादली मोडे से जहांगीरपुरी के बीच धीमी गति से मेट्रो का परिचालन हुआ। लिहाजा, येलो लाइन पर पूरे दिन मेट्रो का परिचालन प्रभावित रहा। इससे यात्रियों को सफर में परेशानी का सामना करना पड़ा।

दो दिन में दूसरी चोरी की घटना

यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य दिनों के मुकाबले अधिक समय लगा। यह दो दिनों में दिल्ली मेट्रो के कॉरिडोर पर केवल चोरी के प्रयास के कारण मेट्रो का परिचालन प्रभावित होने की दूसरी घटना है। 49.02 किलोमीटर लंबी येलो लाइन पर समयपुर बादली व रोहिणी सेक्टर-18 के बाद तीसरा स्टेशन हैदरपुर बादली मोड व चौथा स्टेशन जहांगीरपुरी है।

छोटे से हिस्से में ज्यादा प्रभावित रही मेट्रो

थोड़ी राहत की बात यह रही कि इस छोटे से हिस्से पर ही परिचालन ज्यादा प्रभावित रहा। येलो लाइन के बाकी हिस्से पर मेट्रो की फ्रिक्वेंसी थोड़ी प्रभावित हुई। फिर भी जहांगीरपुरी से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम तक परिचालन काफी हद तक सामान्य रहा।

स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़

हैदरपुर बादली मोड से जहांगीरपुरी के बीच मेट्रो धीमी चलने के कारण मेट्रो थोड़ी देर से उपलब्ध हो रही थी। इस वजह समयपुरी बादली, रोहिणी सेक्टर-18, हैदरपुर बादली मोड, जहांगीरपुरी सहित येलो के कई स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ अधिक रही।

DMRC ने क्या कहा?

डीएमआरसी का कहना है कि यात्रियों को ज्यादा परेशानी न हो इसके लिए प्रभावित हिस्से पर धीमी गति से परिचालन जारी रखा गया। रात में मेट्रो का परिचालन बंद होने के बाद सिग्नल सिस्टम के केबल को ठीक कर लिया जाएगा। एक दिन पहले रेड लाइन पर वेलकम से सीलमपुर के बीच सिग्नल के केबल चोरी के प्रयास के कारण मेट्रो का परिचालन प्रभावित रहा था।

पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं

24 अगस्त को भी रेड लाइन पर ऐसी घटना हुई थी। मेट्रो के एलिवेडेट कॉरिडोर पर केबल चोरी एक बड़ी समस्या रही है। मजेंटा लाइन पर मेट्रो का परिचालन शुरू होने के बाद वर्ष 2018 में शुरुआती तीन माह में केबल चोरी की 25 घटनाएं हुई थीं और करीब 4000 मीटर केबल चोरी हुई थी।

जनवरी 2020 से जनवरी 2023 के बीच विभिन्न कॉरिडोर पर केबल चोरी की 174 घटनाएं हुई थीं और 72 आरोपित गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद भी घटनाएं नहीं थमी।

स्वतंत्रता और सड़क सुरक्षा: आज भी एक संघर्ष की आवश्यकता

डॉ. अंकुर शरण

1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आज भी हम कई मायनों में प्राकृतिक और सामाजिक तौर पर गुलाम हैं। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के 77 साल बाद भी, हम ऐसे मुद्दों से जूझ रहे हैं जो हमें असल में बंधनों में जकड़े हुए हैं। इनमें से एक प्रमुख मुद्दा है सड़क सुरक्षा, जहां हर साल हजारों लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में चली जाती है। इस समस्या का समाधान हमारी स्वतंत्रता संग्राम के नायकों जैसे साहसिक और निर्भीक लोगों द्वारा ही संभव है। जिस तरह से शहीद भगत सिंह और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, वैसे ही आज हमें ऐसे वीरों की आवश्यकता है जो हमारे देश को सड़क दुर्घटनाओं की गुलामी से मुक्त कर सकें।

सड़क दुर्घटनाएं: एक अदृश्य गुलामी

आज भारत में सड़क दुर्घटनाएं एक बड़े संकट का रूप ले चुकी हैं। हर साल, लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल होते हैं या अपनी जान गंवाते हैं। ये दुर्घटनाएं केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हमारे समाज की एक बड़ी विफलता हैं। इन घटनाओं से न केवल प्रभावित व्यक्ति बल्कि उनके परिवार, दोस्त और पूरा समाज भी गहरा धक्का महसूस करता है। सड़क दुर्घटनाएं हमारे विकास की गति को रोकने वाली बाधाएं हैं और यह दिखाती हैं कि हम अभी भी एक अदृश्य गुलामी में बंधे हुए हैं।

उदाहरण: सड़क सुरक्षा में सुधार की आवश्यकता

भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर स्थिति चिंताजनक है। हर दिन खबरों में किसी न किसी दुर्घटना की सूचना मिलती है, चाहे वह छोटे शहरों की सड़कों पर हो या बड़े महानगरों के व्यस्त मार्गों पर।

भारत में सड़क सुरक्षा के मुद्दों का समाधान बहुत जरूरी है। इसके लिए सड़क कानूनों का पालन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कड़े मापदंड, सड़क इंजीनियरिंग में सुधार, और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है।

भगत सिंह की सोच और आज की आवश्यकता

शहीद भगत सिंह जैसे वीर क्रांतिकारी जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी जान न्योछावर की, हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने समाज की बड़ी समस्याओं को भी उसी संकल्प के साथ हल करें। भगत सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि समाज के लिए कुछ बड़ा करने का साहस दिखाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया, उसी तरह आज हमें अपने समाज को सड़क दुर्घटनाओं की गुलामी से मुक्त करने के लिए संघर्ष करना होगा।

सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक क्रांति

आज के दौर में, सड़क सुरक्षा एक ऐसी क्रांति की मांग करती है जिसमें सरकार, प्रशासन, वाहन चालक और आम नागरिक सभी मिलकर काम करें। सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन करना, छोटे बच्चों को यातायात के नियमों का ज्ञान देना, और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को और सख्त बनाना कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें तुरंत उठाने की जरूरत है।

7 अक्टूबर 1930 को, जब क्रांतिकारी भगत सिंह ने हंसते-हंसते देश के लिए अपना बलिदान दिया, तब पूरा देश उन्हें गर्व से याद करता है। वहीं, आज जब कोई नौजवान सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देता है, तो समाज अक्सर नकारात्मक टिप्पणियां करता है। फर्क साफ है—देश को आज न केवल सच्चे देशभक्तों की जरूरत है, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति भी जागरूक होना होगा। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और एक सुरक्षित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

भगत सिंह जैसे नायकों के बलिदान को याद करते हुए, हमें उनके आदर्शों को अपनाकर सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे वीरों की आवश्यकता है जो इस मुद्दे को गंभीरता से लें और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें। सड़क सुरक्षा की इस जंग में हर नागरिक का योगदान आवश्यक है ताकि हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकें जो न केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो, बल्कि प्राकृतिक और सामाजिक रूप से भी स्वतंत्र हो।

सड़क सुरक्षा के लिए एक नई आजादी की लड़ाई की जरूरत है, जहां हम भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की तरह अपने समाज को जागरूक और सुरक्षित बनाएं। आज, जब हम उनके बलिदान को याद करते हैं, यह समय है कि हम अपने देश को सड़क दुर्घटनाओं की गुलामी से मुक्त करने का संकल्प लें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी शहीद भगत सिंह और उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपनी जान न्योछावर की।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

आदिशक्ति की आराधना में आधुनिकता का तड़का मत लगाओ

आदिशक्ति माँ दुर्गा की उपासना का महापर्व नवरात्रि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें छोटी-छोटी बच्चियों के साथ सभी वर्ग के पुरुष, महिला, लडकियां और युवा इस महारास गरबों की धूमधाम की जान होते हैं। ऐसे धार्मिक उत्सव में माता रानी की भक्ति में सनातन संस्कृति, परम्परा व विरासत के मिले-जुले सामाजिक ताने-बाने की गूंज डांडियों में रहती है। यह नवरात्रि पर्व भारतीय सभ्यता का प्रतीक भी है। धार्मिक समरसता के विभिन्न रंगों में भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ने हेतु सही व सकारात्मक ऊर्जा के साथ संस्कारों की पैरवी नवरात्रि में आदिशक्ति की उपासना और शक्ति की आराधना का यह त्योहार जीवन को खुशहाल बनाने में सहयोग भी करता है, लेकिन इस पर्व की भक्ति के रंग में आज आधुनिकता का तड़का लग रहा है, जिससे फूहड़ता व दूषित संस्कृति के नजारे देखना-मिलना आम बात हो रही है। फिल्मी गानों व डीजे की धुन पर अब पारम्परिक गरबों में 'ताली' वाली गूंज गुमनाम हो चुकी है। भक्ति की वही पुरानी परम्परा साड़ी, चुनरी ओर राज्यों के अपने- अपने पारम्परिक पहनावे की संस्कृति का महत्व अपने-आपमें बहुत ही प्रभावी है, पर आज के दौर में यह सबके सब आधुनिकता के आगे नतमस्तक हो चुके हैं।

दूसरी ओर कपड़ों के नाम पर फूहड़ता का फैशन समाज में आखिर क्यों स्वीकारा जा रहा है ? युवा वर्ग को अगर समझाया जाता है तो वह इसमें 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के नाम पर विरोधी हो जाते हैं। वर्तमान में २ अलग-अलग विचारों की विभिन्नता फैल रही है, जिस पर चिंतन जरूरी है, क्योंकि एक तरफ दूषित मानसिकता व दूसरी ओर संस्कृति को बचाने हेतु सकारात्मक सोच यानी दोनों के

लिए त्योहार मनाने के अलग- अलग मायने। आदिशक्ति माँ की ऐसी आराधना भक्ति किस काम की, जो हमारी संस्कृति व संस्कारों को दूषित कर रही हो।

अत्याधुनिक फैशन व संस्कृति ने हमें और युवा पीढ़ी को बहुत आधुनिक बना दिया है, जिसके कारण ही पर्व-त्योहार पर ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, जिससे सभी को शर्मिंदा होना पड़ता है।

सबको समझना होगा कि माँ की आराधना परिवार, समाज और धर्म की एकता की प्रतीक है। इसे फूहड़पन व अश्लीलता का जामा पहना बहुत गलत है। गरबा नृत्य को महोत्सव के रुप में मनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। दोनों पहलू के इस चित्रण में अलग- अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, पर भक्ति की पवित्रता मानो धूमिल होती जा रही है। अब गरबा 'इवेंट' यानी कार्यक्रम बनता जा रहा है। नैतिक शिक्षा व धर्मिक ग्रंथों की जो शिक्षा नृत्य-संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम व नाटकों के माध्यम से बताई जाती थी, जो गरबे पूरे परिवार के साथ करते थे और मिल-जुल कर देखते थे, वह बात अब नहीं रही, क्योंकि आदिशक्ति की उपासना श्रेणी के हिसाब से गरबा पांडालों में दिखाई देने लगी है। बच्चे अलग, बुजुर्ग महिला अलग और युवक-युवती एकसाथ' ऐसे ही माहौल में गरबा पांडालों में आजकल आयोजन होते हैं। यह कहां जा रहे हैं हम ? सामाजिक जिम्मेदारी व उत्सव के प्रति हमारी यह उदासीनता बहुत दुखद है। इस विषय पर जनजागरण जरूरी है। नवरात्रि पर्व की इस उंमगता को आधुनिकता में धूमिल मत होने दो। इस पर्व की भक्ति की पवित्रता व आदिशक्ति की आराधना में आधुनिकता का तड़का मत लगाओ। भारतीय परम्परा के अनुसार शालीनता से मिल-जुलकर त्योहार मनाया जाए तो उत्सव का मजा दोगुना हो जाएगा।

हरिहर सिंह चौहान जबरी बाग़
नसिया इन्दौर मध्यप्रदेश 452001

दिल्ली पुलिस की लेडी सिंघम चला रहीं आत्मरक्षा की पाठशाला, आत्मविश्वास की 'किरण' बनकर जगा रहीं सुरक्षा का भरोसा

दिल्ली पुलिस की लेडी सिंघम किरण सेठी महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बना रही हैं। वह दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में महिला डॉक्टरों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही हैं। वह देह व्यापार के दलदल में फंसी महिलाओं को मुक्त कराकर उन्हें स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रही हैं। किरण सेठी ने अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है।

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में युवा प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। घटना के दो माह बाद भी आक्रोश थम नहीं रहा है। डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर सहमे हुए हैं। दिल्ली में महिला डॉक्टर्स को संबल देने के लिए लेडी सिंघम के रूप में पहचान रखने वाली सब-इंस्पेक्टर किरण सेठी ने जिम्मा उठाया है।

शहर की महिला चिकित्सा पेशेवरों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए गंभीरता से काम कर रही हैं। दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में पूर्वविशेषज्ञशिव कुमार कोहली के साथ मिलकर सत्र आयोजित कर महिला डॉक्टर्स को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दे रही हैं। सत्र के माध्यम से अब तक तीन हजार से अधिक महिला डाक्टर्स व नर्स प्रशिक्षण ले चुकी हैं और किरण की इस पहल से अपने डर को आत्मविश्वास में बदल रही हैं।

रेजिडेंट डाक्टर्स का कहना है कि सत्र में भाग लेकर वह मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रही हैं। किरण अब तक एम्स, सफदरजंग अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, एलएन और जीबी पंत, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, लेडी हार्डिंन और कई बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सत्र आयोजित कर चुकी हैं।

दलदल से निकाल संबल भरतीं

दिल्ली के श्रद्धानंद मार्ग स्थित महिला पुलिस चौकी इंजार्च किरण सेठी के इस संबल की कहानी कुछ यूं शुरू हुई थी। किरण को बचपन से ही पढ़ाई के साथ खेलने-कूदने का शौक था। वह परिवार में सबसे बड़ी हैं और उनके दो छोटे भाई-बहन हैं। पिता को किसी ने जहर दिया था, जिससे उनकी आवाज चली गई थी। तब किरण अपने बचपन को गढ़ रही थीं, मां रणजीत नगर में रेस्तरां चलाती थीं।

छोटी से उम्र में ही घर की जिम्मेदारियों से घिरीं किरण ने पढ़ाई के साथ-साथ अपनी मां का हाथ बंटाना शुरू कर दिया था। सेल्फ डिफेंस में महारत हासिल कर चुकीं किरण 12वीं पास करने के बाद महज 19 साल की उम्र में सिपाही के पद भर्ती हुईं अब तक अपने करियर में दस लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं।

इसके अलावा वह दिव्यांगों को भी सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण देती हैं। वह इस बात पर जोर देती हैं कि स्कूलों में बच्चियों को पढ़ाई के साथ-साथ इस बात की भी शिक्षा देनी चाहिए कि उन्हें मजबूत कैसे बनना है। साथ ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सामान्य क्लास की तरह होनी चाहिए, ताकि उन्हें जीवन के शुरुआती चरणों में ही खुद को सुरक्षित रखने के बारे में सिखाया जाए।

किरण दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में देह व्यापार के दलदल में जबरन फंसाई गई लगभग 50 से अधिक महिलाओं व नाबालिगों को अब तक मुक्त करा चुकी हैं। उन्होंने नशे के आदी, सेक्स वर्कर्स और दिव्यांगों को योगा की ट्रेनिंग देकर सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित किया।

आज खुद को सुरक्षित महसूस कर रहीं सेक्स वर्कर्स

किरण सेठी वर्ष 2020 से सेक्स वर्कर्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही हैं, साथ ही उन्हें स्किल डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाता है। श्रद्धानंद मार्ग स्थित अपनी पोस्टिंग के बाद किरण ने देखा कि वहां काम कर रहीं सेक्स वर्कर्स मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर हैं। उन्होंने डॉक्टर्स से उनकी काउंसलिंग कराई और उनकी परेशानियों सुनीं। यही कारण है कि आज इन सेक्स वर्कर्स को सिलाई मशीन चलाना, मिट्टी के दीपक बनाना, लिफाफे बनाना, आदि गुर सिखाए जाते हैं।

कई बार उनके द्वारा बनाए सामान को मार्केट में सेल भी किया गया। इसको बेचकर जो भी पैसे मिले उसे इनमें बांटा गया। इसका उद्देश्य उन्हें यह बताना था कि देह व्यापार छोड़कर इस तरह के काम कर के भी आजीविका चलाई जा सकती है। इसके अलावा वह जल्द ही देह व्यापार में शामिल महिलाओं के लिए ई-रिक्शा की भी व्यवस्था करने वाली हैं।

उनका मानना है कि ई-रिक्शा चलाने से इस तरह के व्यापार में लिप्त महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जूडो और कराटे में हैं ब्लैक बेल्ट किरण ने स्कूली दिनों से ही जूडो की ट्रेनिंग लेना शुरू किया था और 57 साल की उम्र में भी वह अपनी फिटनेस और काम के प्रति खुद को झोंक देने के अपने जज्बे से लाखों लोगों के लिए मिसाल बन रही हैं।

उन्होंने हमेशा खुद को दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रखा। जूडो और कराटे में ब्लैक बेल्ट होने के बाद वह न केवल सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाती हैं, बल्कि योग और एरोबिक्स के जरिए फिटनेस को भी बढ़ावा देती हैं। बेहतरीन किकबाक्सर के तौर पर अपनी पहचान बनाने वालीं किरण ने 1999 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया था। पुरुषों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने वाली पहली महिला वैसे किरण सेठी कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं, मगर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह दिल्ली पुलिस की ऐसी पहली महिला पुलिस अधिकारी हैं, जिन्होंने पुरुषों को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है।

माँ के नवरात्र

नवरात्रि का पर्व नवनिर्माण के लिए होता है, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक।

आदिकाल से ही मनुष्य की प्रकृति शक्ति साधना की रही है। शक्ति साधना का प्रथम रूप दुर्गा अर्थात 'माँ' ही मानी जाती है। मनुष्य तो क्या देवी-देवता, यक्ष-किन्नर और सृष्टि का प्रत्येक जीव भी अपने संकट निवारण के लिए 'माँ' अर्थात दुर्गा' को ही पुकारते हैं।

हमारे देश में 'माँ' को 'शक्ति' का रूप माना गया है और वेदों में 'माँ' को सर्वप्रथम पूजनीय कहा है। क्योंकि पृथ्वी के प्रत्येक जीव के प्रत्येक नवजात का पहला भाव- एहसास- स्पर्श- शब्द यदि कोई है तो वह है ₹माँ₹..//

इस श्लोक में भी इष्टदेव को सर्वप्रथम 'माँ' के रूप में ही उद्बोधित किया गया है – "त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या, द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम्मम देव देव.."।।

हमारे वेद, पुराण, दर्शनशास्त्र, स्मृतियाँ, महाकाव्य, उपनिषद आदि सब 'माँ' की अपार महिमा के गुणगान से भरे पड़े हैं। असंख्य ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, पंडितों, महात्माओं, विद्वानों, दर्शनशास्त्रियों, साहित्यकारों आदि ने भी 'माँ' के प्रति पैदा होने

वाली अनुभूतियों को कलमबद्ध करने का भरसक प्रयास किया है। इन सबके बाद भी 'माँ' शब्द की समग्र परिभाषा और उसकी अनन्त महिमा को आज तक कोई शब्दों में नहीं पिरो पाया है, क्योंकि माँ अनन्त है, माँ महान है, माँ सर्वोपरि है, माँ पूजनीय- वंदनीय है//

मां कात्यायनी को बेहद प्रिय है यह रंग, नवरात्र के छठे दिन बेस्ट रहेंगे 5 आउटफिट्स

नवरात्र के छठे दिन मां भगवती को देवी कात्यायनी के रूप में पूजा जाता है जिन्हें लाल रंग बेहद प्रिय है। बता दें लाल रंग धन और समृद्धि के साथ-साथ प्रेम और शक्ति का भी प्रतीक है इसलिए नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करते समय आप भी लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं।

नई दिल्ली। नवरात्र के छठे दिन लाल रंग (Navratri Day 6 Colour) के कपड़े पहनना न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से जरूरी होता है बल्कि यह खूबसूरती के लिहाज से भी काफी जंचता है। तीज-त्योहार के मौके पर वैसे भी लाल रंग खूब पहना जाता है और खास बात है कि यह हर उम्र की महिलाओं पर सूट भी करता है। ऐसे में, इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे बेहतरीन आउटफिट आइडियाज देने जा रहे हैं जिन्हें इन दिन अपनाकर आप नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी (Maa Katyayani) की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।

लाल साड़ी

नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आप लाल रंग की साड़ी पहन सकती हैं। बनारसी या सिल्क साड़ी न सिर्फ आपको क्लासी लुक देती हैं बल्कि आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम भी करती हैं। आप इस साड़ी को ट्रेंडी ज्वेलरी के साथ पेयर करके अपने लुक को और भी स्टाइलिश बना सकती हैं।

लाल सलवार-सूट

नवरात्र के छठे दिन आप मां कात्यायनी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग का सलवार सूट भी पहन सकती हैं। लाल रंग के साथ गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन हमेशा से ही खूबसूरत लगता है। ऐसे में, आप लाल रंग का सलवार सूट गोल्डन जरी या एम्ब्रॉयडरी वाले दुपट्टे के साथ पेयर कर सकती हैं। इस कॉम्बिनेशन से आपका लुक और भी शानदार लगेगा।

लाल शरारा सेट

शरारा सेट इन दिनों फैशन की दुनिया में काफी ट्रेंड में है। ऐसे में, आप भी नवरात्र के छठे दिन इसके साथ एक अनोखा लुक क्रिएट कर सकती हैं। इस लाल रंग के शरारा सेट के साथ आप कंट्रास्टिंग या मिरर वर्क वाले दुपट्टे को कैरी करके अपने लुक को और भी ज्यादा खास बना सकती हैं।

रेड कुर्ता सेट

लाल रंग का सूट हर उम्र की महिलाओं पर खूब जंचता है। ऐसे में, आप भी नवरात्र के छठे दिन इस रंग का कुर्ता सेट पहनकर मां कात्यायनी की पूजा में शामिल हो सकती हैं। खास बात है कि आप प्लाजो के साथ इसे पेयर करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी।

रेड केप

नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी के प्रिय लाल रंग को आउटफिट का हिस्सा बनाना चाहती हैं, तो आप लाल रंग की प्लेन स्कर्ट के साथ एक कॉन्ट्रास्टिंग रंग का क्रॉप टॉप पहन सकती हैं। इसके ऊपर लाल मरून रंग का एम्ब्रॉयडरी वाला केप पहनकर आपका लुक और भी खूबसूरत हो जाएगा और यह कॉम्बिनेशन आप पर खूब जंचेगा।

पर्यावरण पाठशाला : दो पौधों की कहानी - गमले का पौधा और बगीचे का पौधा

अंकुर

एक बार की बात है, एक सुंदर बगीचे के एक कोने में एक गमले का पौधा और एक प्राकृतिक बगीचे का पौधा एक साथ रहते थे। गमले का पौधा छोटी जगह में उगता था, जबकि बगीचे का पौधा जमीन में जड़ें फैला कर पूरे बगीचे में अपनी शाखाएं फैलाने में सक्षम था।

गमले का पौधा अक्सर बगीचे के पौधे से बातें करता और उससे अपनी समस्याएं साझा करता। एक दिन उसने कहा, ₹मैं हमेशा तुम्हें देखता हूं, तुम कितने खुश और स्वतंत्र हो। तुम्हारी जड़ें गहरी हैं, और तुम्हें हर दिन ताज़ी हवा, बारिश और मिट्टी से पोषक तत्व मिलते हैं। जबकि मैं इस छोटे से गमले में बंधा हुआ हूं, मेरी जड़ें ज्यादा फैल नहीं सकतीं और मुझे इंसानों पर निर्भर रहना पड़ता है।

बगीचे का पौधा मुस्कुराया और गमले के पौधे से बोला, ₹यह सच है कि मुझे प्रकृति से सब कुछ मिलता है, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हें बहुत प्यार और देखभाल मिलती है। लोग तुम्हें नियमित रूप से पानी देते हैं, तुम्हारी मिट्टी बदलते हैं, और तुम्हारे ऊपर ध्यान देते हैं। तुम घरों की शोभा बढ़ाते हो और लोगों के दिलों में खास जगह बनाते हो।

गमले का पौधा थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, ₹लेकिन मेरी जड़ें तो सीमित हैं। मैं ज्यादा ऊंचा नहीं बढ़ सकता और मेरा जीवन भी बहुत छोटा होगा। मुझे हर वक्त डर लगता है कि अगर किसी दिन इंसान मेरी देखभाल न करें, तो मैं सूख जाऊंगा।

बगीचे के पौधे ने गहरी सांस ली और कहा, ₹हर जीवन की अपनी चुनौतियाँ और खासियतें होती हैं। मुझे प्रकृति ने ढेर सारे अवसर दिए हैं, लेकिन मुझे कई खतरों का सामना भी करना पड़ता है। कभी-कभी सूखा पड़ता है, तेज हवाएं और तूफान आते हैं, और कीड़े-मकोड़े मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन मैं अपने जीवन का आनंद लेता हूं क्योंकि मुझे धरती की स्थिरता और स्वतंत्रता का अनुभव होता है।

गमले का पौधा थोड़ा शांत हुआ और कहा, शायद तुम सही हो। हर पौधे का अपना सफर और संघर्ष होता है। मुझे खुश रहना चाहिए कि मैं उन लोगों के दिलों को खुश करता हूं जो मेरी देखभाल करते हैं।

बगीचे के पौधे ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ₹हां, और याद रखो, चाहे हम जहां भी हों, हमारी असली जिम्मेदारी प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीना है। हम सभी अपनी-अपनी जगह पर पर्यावरण का हिस्सा हैं और इसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है।

और इस तरह गमले का पौधा और बगीचे का पौधा, दोनों अपनी-अपनी परिस्थितियों में खुश रहने लगे, यह समझते हुए कि हर जीवन की अपनी विशेषताएं और चुनौतियाँ होती हैं। दोनों एक-दूसरे का सम्मान करते हुए और अपने-अपने जीवन को संवारते हुए प्रकृति का हिस्सा बने रहे।

indiangreenbuddy@gmail.com

गृह मंत्री अमित शाह ने की छत्तीसगढ़ की नक्सल विरोधी रणनीति की सराहना, कहा- बेहतरीन काम कर रही राज्य सरकार

सुषमा रानी

गृह मंत्री शाह ने विशेष रूप से हाल ही में हुए नक्सली मुठभेड़ का उल्लेख किया जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस ने 31 नक्सलियों को ढेर किया था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस डीआरजी और बस्तर बटालियन के जवानों ने बेहतरीन तालमेल और खुफिया जानकारी के साथ इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह अभियान राज्य सरकार की रणनीति खुफिया तंत्र और केंद्रीय बलों के सहयोग का बेहतरीन उदाहरण है।

नई दिल्ली। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सोमवार को नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी टीम के साहसिक प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सल उन्मूलन के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों को सराहते हुए मुख्यमंत्री और उनकी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर कार्य कर रही है, जिससे नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। शाह ने कहा कि हमने डिफेंसिव नीति को छोड़कर आक्रमक नीति को अपनाया है।

बैठक के दौरान गृह मंत्री शाह ने विशेष रूप से हाल ही में हुए नक्सली मुठभेड़ का उल्लेख किया, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस ने 31 नक्सलियों को ढेर किया था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस, डीआरजी और बस्तर बटालियन के जवानों ने बेहतरीन तालमेल और खुफिया जानकारी के साथ इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह नक्सल उन्मूलन अभियान राज्य सरकार की रणनीति, खुफिया तंत्र और केंद्रीय बलों के सहयोग का बेहतरीन उदाहरण है।

पिछले नौ महीनों में 194 से अधिक माओवादी मारे गए

गृह मंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले नौ महीनों में 194 से अधिक माओवादी मारे गए हैं, 800 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारियां हुई हैं और 738 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और मुख्यमंत्री साय व उनकी टीम सराहना के योग्य है। उन्होंने कहा कि "डबल इंजन की सरकार" के सहयोग से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे वहां के लोग मुख्यधारा में लौट रहे हैं।

गांवों में पहुंचा विकास

अमित शाह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सहित सभी नक्सल प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि इन क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित गांवों में विकास का नया अभियान चलाया, जिससे गांवों में विकास पहुंचा है। सरकार ने नक्सलियों के वित्तीय पोषण को भी रोका है।

डिलीवरी ब्वाय की सड़क हादसे में मौत, पैदल रोड क्रॉस करते वक्त हुआ हादसा

दिल्ली के मुनिरका फ्लाईओवर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 27 वर्षीय जोमैटो डिलीवरी ब्वॉय हरेंद्र की मौत हो गई। पैदल सड़क पार करते समय उन्हें एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगा लिया है और किशनगढ़ थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।

दक्षिणी दिल्ली। मुनिरका फ्लाईओवर के पास सोमवार तड़के 27 वर्षीय जोमैटो डिलीवरी ब्वाय हरेंद्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह अपनी बाइक किनारे खड़ी कर पैदल ही सड़क पार कर रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। मृतक के पिता सुरेश चंद शर्मा डीडीए में क्लास-4 कैडर में कार्यरत हैं।

पुलिस के मुताबिक तड़के 2:45 बजे आउटर रिंग, फुट ब्रिज के नीचे डीडीए फ्लैट्स गेट मुनिरका में सड़क हादसे को लेकर पीसीआर कॉल आई। टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और मौके से भाग गया। घायल को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगा लिया

मृतक की पहचान हरेंद्र पुत्र सुरेश चंद शर्मा निवासी मकान नंबर 751, सेक्टर 1, आरके पुरम, नई दिल्ली के रूप में हुई। मृतक जोमैटो में डिलीवरी ब्वाय के तौर पर काम करता था। वह शादीशुदा था और उसका 6 महीने का बेटा है। पत्नी चेतना गृहणी हैं जबकि पिता डीडीए में क्लास 4 कैडर में कार्यरत हैं। पुलिस ने टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगा लिया है। किशनगढ़ थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आगे की जांच जारी है।

इस रामलीला ने बनाया रिकॉर्ड, 41 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा

परिवहन विशेष न्यूज

अमेरिका लंदनबांग्लादेश जर्मनी चीनसाउथ अफ्रीकासाउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया स्विट्जरलैंड कनाडा थाईलैंड मलेशिया इराक अफगानिस्तान और कई देशों मे इसका प्रसारण किया जा रहा है। अयोध्या की रामलीला में जाने माने बॉलीवुड के फिल्म स्टार काम कर रहे हैं जैसे रितु शिवपुरी रजा मुराद भाग्यश्री मनीष शर्मा अंजली शुक्ला मैडोना पायल गोगा कपूर राकेश बेदी और रितु सिंघा ने भी अपने अभिनय से अयोध्या वासियों और राम भक्तों का दिल जीता।

अयोध्या की रामलीला ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। बीते तीन दिनों में ही ऑनलाइन प्लेटफार्म पर 41 करोड़ दर्शकों ने रामलीला देखी और रिकॉर्ड बना दिया। दुनिया के 40 देशों में 26 भाषाओं में इसका प्रसारण हो रहा है। इस रामलीला को 42 से ज्यादा देशों में दिखाया जा रहा है।अमेरिका, लंदन,बांग्लादेश, जर्मनी चीन,साउथ अफ्रीका,साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया स्विट्जरलैंड, कनाडा, थाईलैंड मलेशिया, इराक, अफगानिस्तान और कई देशों मे इसका प्रसारण किया जा रहा है। अयोध्या की रामलीला में कई जाने माने बॉलीवुड के फिल्म स्टार काम करते हैं जैसे रितु शिवपुरी, मनोज तिवारी,रजा मुराद, भाग्यश्री, मनीष शर्मा, अंजली शुक्ला, मैडोना, पायल गोगा कपूर, राकेश बेदी इस बार मिस यूनिवर्स रितु सिंघा ने भी अपने अभिनय से अयोध्या वासियों और राम भक्तों का दिल जीता।

अयोध्या की रामलीला में सांसद भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी- 'परशुराम' की भूमिका राजा मुराद- 'राजा दशरथ' की भूमिका अदा कर रहे हैं। वेद सागर और मंगिशा- भगवान राम और मां सीता की भूमिका निभा रही है। सुभाष मलिक और महासचिव शुभम मलिक ने बताया कि राकेश बेदी- 'राजा जनक' की भूमिका निभा रहे हैं । जाने माने बॉलीवुड के एक्टर (मनीष शर्मा) रावण की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पॉपुलर चेहरों को जोड़ने के पीछे हमारा मकसद है कि लोग रामलीला से बड़ी तादाद में जुड़ें साथ ही युवाओं का भी रामलीला के प्रति रूझान अधिक से अधिक बढे.। इस बार की रामलीला में सबसे ज्यादा फिल्म स्टार काम कर रहे हैं।

वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल ने विश्व हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर दिवस मनाया

जीवन के अंत में करुणामय देखभाल प्रदान करने के लिए हमारा समर्पण अटूट है : डॉ. वंदना तलवार

पिछले एक दशक में हमने जो प्रगति की है, वह सराहनीय है, लेकिन अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है : डॉ. वंदना तलवार

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल ने विश्व हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर दिवस मनाया, जिसमें ₹संकल्प के 10 साल बाद: हम कैसे कर रहे हैं ?₹ थीम पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक एमएस डॉ. वंदना तलवार मौजूद रही। पैलिएटिव पेन क्लिनिक की प्रभारी डॉ. सवीना रहेजा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, छात्रों और रोगियों ने पिछले एक दशक में पैलिएटिव केयर में हुई प्रगति पर विचार किया।

अपने संबोधन में, डॉ. वंदना तलवार ने पैलिएटिव केयर सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अस्पताल की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ₹जीवन के अंत में करुणामय देखभाल प्रदान करने के लिए हमारा समर्पण अटूट है। पिछले एक दशक में हमने जो प्रगति की है, वह सराहनीय है, लेकिन अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है।₹ प्रिंसिपल डॉ. गीतिका खन्ना ने प्रशामक देखभाल शिक्षा और सेवा वितरण में संस्थान की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की आयोजक डॉ. सवीना रहेजा ने दर्द निवारक क्लिनिक की स्थापना और संचालन में चुनौतियों और सफलताओं के बारे में बात की, तथा रोगी देखभाल में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

कार्यक्रम का एक उल्लेखनीय आकर्षण उन रोगियों का सम्मान था, जिन्हें अस्पताल की प्रशामक देखभाल सेवाओं से लाभ मिला है। जागरूकता अभियान में एक रचनात्मक आयाम जोड़ते हुए, मेडिकल छात्रों ने प्रशामक देखभाल के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए एक आकर्षक ₹नुक्कड़ नाटक₹ (स्ट्रीट प्ले) प्रस्तुत किया। इस आयोजन ने प्रशामक देखभाल सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अस्पताल की प्रतिबद्धता को सफलतापूर्वक मजबूत किया और स्वास्थ्य सेवा के इस महत्वपूर्ण पहलू के बारे में जागरूकता बढ़ाई।

आज भारत में बन रहा है आईफोन, क्या श्रम सुधार से मिलेगी मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार?

परिवहन विशेष न्यूज

मेक इन इंडिया पहल ने भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नए सिरे से मजबूत किया है। वर्ष 2014 में जब भारत का मैन्युफैक्चरिंग बेस गिरावट पर था तब इस पहल ने उसे न सिर्फ रोका बल्कि GDP में इसकी हिस्सेदारी 17% तक बनाए रखी। अभी भी श्रम सुधारों और लॉजिस्टिक्स में चुनौतियां हैं लेकिन सरकार की प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम से यह क्षेत्र आगे बढ़ रहा है।

नई दिल्ली। मेक इन इंडिया पहल से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई जान आई है। यह सही है कि 10 वर्ष पहले भी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 17 प्रतिशत थी और आज भी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 17 प्रतिशत है, लेकिन इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि मेक इन इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा नहीं मिला है।

आपको सही तस्वीर जानने के लिए 2014 के पहले के आंकड़ों पर गौर करना होगा। 2002 से 2014 के बीच मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े गिर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं भारत में बनने के बजाए बाहर से आयात हो रही थीं। बाहर से आ रही चीजें इतनी सस्ती थीं कि उनका यहां निर्माण करना आर्थिक तौर पर फायदेमंद नहीं था।

भारतीय उद्यमियों ने विदेश में लगाई थीं फैक्ट्रियां

यही वह दौर था, जब बहुत से कारोबारियों ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करके दूसरे देशों में जाकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाईं। यहां तक भारत के ही बहुत से उद्यमियों ने अपनी यूनिट भारत में बंद करके बांग्लादेश में लगाईं और बांग्लादेश ने कपड़ों के निर्यात में भारत को पीछे छोड़ दिया। उस समय भारत का दूसरे देशों से जो व्यापार समझौता था, वह एकतरफा था। जैसे थाईलैंड और आसियान के साथ।

इस समझौते से फायदा सिर्फ दूसरे देशों को हो रहा था और व्यापार संतुलन भारत के खिलाफ था। इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो रही थी। इस स्थिति को बदलने के लिए 2014 में मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया। अगर मेक इन इंडिया न होता तो मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा गिर कर 10-12 प्रतिशत पर आ जाता।

मेक इन इंडिया से कैसे फायदा हुआ ?

मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मेक इन इंडिया से कैसे फायदा हुआ है। इसे देखने का एक और तरीका है। साल 2014 में भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 17 प्रतिशत थी। उस समय हमारी जीडीपी का आकार 2 लाख करोड़ डॉलर था। इसका 17 प्रतिशत हुआ 35 अरब डॉलर।

आज हमारी जीडीपी का आकार 3.2 लाख करोड़ डॉलर है। इसका 17 प्रतिशत हुआ करीब 50 अरब डॉलर। ऐसे में मेक इन इंडिया ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गिरावट को न सिर्फ रोका है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग बेस का विस्तार किया है।

मेक इन इंडिया की सफलता का आकलन आप ऐसे कर सकते हैं कि 10 वर्ष पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत में आईफोन बन सकता है। एपल जैसी बड़ी कंपनी के लिए यह सोचना भी मुश्किल था कि वह भारत में आईफोन बनाए। यह सोच आई है सिर्फ मेक इन इंडिया की वजह से।

मेक इन इंडिया के बाद जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम शुरू की गई है। इसमें उत्पाद के हिसाब से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैसे किसी उत्पाद की इंडस्ट्री को छूट देने की जरूरत है तो उसे छूट दी जा रही है।

इसी तरह अगर किसी को फैक्ट्री लगाने में लगने वाली पूंजी में मदद की जरूरत है तो इसमें भी सरकार मदद कर रही है। जैसे सेमीकंडक्टर के लिए किया है, इलेक्ट्रानिक्स, मेडिकल डिवाइस और टेक्सटाइल के लिए किया है। इसमें सरकार कह रही है कि आप जो फैक्ट्री लगा रहे हैं। निवेश कर रहे हैं, तो आप उत्पाद बनाकर निर्यात करिये। निर्यात पर आपका जो खर्चा आएगा उस पर सब्सिडी देंगे। यह निर्यात बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है।

निश्चित तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सामने कई चुनौतियां हैं। आज सबसे बड़ी चुनौती है श्रम सुधारों की है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है और छह माह बाद हड़ताल हो जाती है तो उसकी पूंजी फंस जाएगी। भारत में सबसे बड़ा डर श्रम नियमों को लेकर है। अगर आपने किसी को एक बार नियुक्त कर लिया तो उसको निकालने की प्रक्रिया बहुत जटिल है।

आज भारत में पूंजी की समस्या नहीं है, खरीदार भी हैं लेकिन श्रमिकों के साथ काम करना एक बड़ी समस्या है। दूसरी चुनौती है भूमि की उपलब्धता। खासकर उपयुक्त जमीन की। जहां पर उत्पाद के परिवहन के लिए ट्रक उपलब्ध हों। एयरपोर्ट नजदीक हो और रेलवे की कनेक्टिविटी भी हो। भारत में लॉजिस्टिक्स की चुनौतियां भी हैं।

(डेलाइट इंडिया के पार्टनर एमएस मनी से बातचीत)

जेपी विश टाउन में निजी आयोजन के खिलाफ स्थानीय निवासियों की शिकायत पर एनजीटी ने कार्रवाई के आदेश दिए

आदेश के अनुसार मामला खेल मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम से संबंधित है जहां बास्केट बॉल टेनिस कोर्ट आदि सहित विभिन्न खेल कोर्ट हैं। याचिका का हवाला देते हुए आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने यह दलील दी है कि उक्त सार्वजनिक पार्क/मनोरंजक क्षेत्र सेक्टर 128 स्थित टाउनशिप का मुख्य स्थान है और हरित क्षेत्र में स्थित इस जगह पर दुर्गा पूजा की आड़ में व्यावसायिक गतिविधियां होंगी।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को नोएडा सेक्टर 128 में जेपी विश टाउन सोसायटी के निवासी की शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। नोएडा के पुलिस आयुक्त भी इस मामले में एक पक्ष हैं। आदेश के अनुसार मामला खेल मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम से संबंधित है जहां बास्केट बॉल, टेनिस कोर्ट आदि सहित विभिन्न खेल कोर्ट हैं। याचिका का हवाला देते हुए आदेश में कहा गया है कि ₹याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने यह दलील दी है कि उक्त सार्वजनिक पार्क/मनोरंजक क्षेत्र सेक्टर 128 स्थित टाउनशिप का मुख्य स्थान है और हरित क्षेत्र में स्थित इस जगह पर दुर्गा पूजा की आड़ में व्यावसायिक गतिविधियां होंगी।

इसके जवाब में, एनजीटी ने आदेश दिया है ₹रिकॉर्ड दर्शाता है कि आवेदक ने प्रतिवादी संख्या 2 (नोएडा प्राधिकरण) को दिनांक 28.08.2024 को एक विस्तृत शिकायत की है। एनजीटी ने आदेश दिया, ₹ओए को तदनुसार प्रतिवादी नंबर 2 को आवेदक की दिनांक 28.08.2024 की शिकायत पर शीघ्रता से विचार करने और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।₹ग्रीन स्पेस में कार्यों पर रोक लगाने का एनजीटी का आदेश पहले से ही है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि आपत्तियों के बावजूद और आदेश पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। निवासियों का दावा है कि कथित पूजा दुर्गा पूजा कम बल्कि एक निजी व्यावसायिक कार्यक्रम अधिक है। खेल मैदान में बन रहे स्थाई शौचालय से भी निवासी खुश नहीं हैं। बीते शनिवार को सब डिविजन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की।

परिणाम से पहले हुड्डा फैमिली की CM पद के लिए लॉबिंग, दिल्ली पहुंचे सैलजा, दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा

कुमारी सैलजा ने मतगणना से पहले कोई ऐसा विवादित बयान नहीं दिया जिससे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की परेशानी बढ़े। सैलजा ने बड़े ही सहज अंदाज में कहा कि ना तो मैं और ना ही कोई दूसरा मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कह सकता है। यह सिर्फ कांग्रेस हाईकमान का फैसला होगा कि वह किसे मुख्यमंत्री बनाता है।

परिवहन विशेष न्यूज

चंडीगढ़। हरियाणा में मतगणना से एक दिन पहले मुख्यमंत्री पद की लाबिंग के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी सैलजा दिल्ली पहुंच गए हैं। पिछले कई दिनों से आराम कर रहे कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात हुई, जिसके बाद हुड्डा व दीपेंद्र ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ दिल्ली में प्रदेश की नई राजनीतिक स्थिति और एक्जिट पोल के नतीजों पर विस्तृत चर्चा की।

मंगलवार को मतगणना पूरी होने के बाद नतीजे आते ही चुनाव जीतने वाले विधायकों के रात तक चंडीगढ़ पहुंच जाने की संभावना है। नई दिल्ली में राजनीतिक विचार विमर्श के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी, जो विधायकों के साथ उनकी पसंद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर उसे कांग्रेस हाईकमान को अवगत कराया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान तय करेगा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।

'हरियाणा में बन रही कांग्रेस की सरकार'

कांग्रेस महासचिव एवं सांसद कुमारी सैलजा ने भी मतगणना से पहले कोई ऐसा विवादित बयान नहीं दिया, जिससे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की परेशानी बढ़े। सैलजा ने बड़े ही सहज अंदाज में कहा कि ना तो मैं और ना ही कोई दूसरा मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कह सकता है।

यह सिर्फ कांग्रेस हाईकमान का फैसला होगा कि वह किसे मुख्यमंत्री बनाता है। सैलजा ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। राज्य में कांग्रेस 60 सीटों से ऊपर का आंकड़ा पार करेगी।

वोट काटू की भूमिका में रहे क्षेत्रीय दल

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नई दिल्ली में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि एक्जिट पोल पांच अक्टूबर को आए थे, लेकिन मैंने एक माह पहले ही कह दिया था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। साथ ही यह भी कहा था कि भाजपा जा रही है।

भाजपा लोकसभा में भी 10 की 10 सीटें आने का दावा कर रही थी, लेकिन नतीजा सबके सामने है। मुख्यमंत्री का फैसला विधायक करेंगे और फिर हाईकमान उन पर अपनी सहमति की मुहर लगाएगा। क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर हुड्डा ने कहा कि मुकाबला ही कांग्रेस व भाजपा का है। इस चुनाव में क्षेत्रीय दल सिर्फ वोट काटू की भूमिका में रहे हैं।

ना मैं टायर्ड, ना रिटायर्ड

प्रदेश की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर कहा कि ना मैं टायर्ड हूं, ना रिटायर्ड हूं। उन्होंने लाडवा में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट फंसी होने की बात कही है। 90 सीटों पर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ने के दावे के साथ हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में जबरदस्त रिस्पांस रहा है।

एक्जिट पोल के आंकलन से बढ़िया रहेंगे चुनाव नतीजे

दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नई दिल्ली में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक्जिट पोल के नतीजे सभी ने देख लिए हैं। इससे भी अच्छा रिजल्ट चुनाव में रहने वाला है।

एक्जिट पोल ने हरियाणा के चुनाव की दिशा बता दी है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारे विधायक और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा मेंडेट मिला था और तभी से माहौल बनना शुरु हो गया था।

बीजेपी के दावे बीजेपी की ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं। उनसे बड़ा झूठ कोई दूसरा नहीं बोल सकता। भाजपा वाले झूठ भी बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं।

कांग्रेस की दो दिन की खुशी बदल जाएगी गम में

मोहन लाल बडौली हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने दावा किया कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दावे मंगलवार की मतगणना में धूल जाएंगे। भाजपा की सरकार बनते ही करीब 25 हजार युवाओं को ज्वाइनिंग कराई जाएगी तथा महिलाओं को 2100 रुपये मासिक की आर्थिक सहायता आरंभ कर दी जाएगी।

बडौली ने कहा कि मंगलवार को सुबह दस बजे तक यह साफ हो जाएगा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। एक्जिट पोल के बाद कांग्रेस की सिर्फ दो दिन की खुशी थी, जो कि मंगलवार को गम में बदल जाएगी। रिजल्ट आने के बाद सब साफ हो जाएगा।

कांग्रेस महासचिव एवं सांसद कुमारी सैलजा ने भी मतगणना से पहले कोई ऐसा विवादित बयान नहीं दिया, जिससे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की परेशानी बढ़े। सैलजा ने बड़े ही सहज अंदाज में कहा कि ना तो मैं और ना ही कोई दूसरा मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कह सकता है।

अल्ट न्यूज से जुड़े मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, यति नरसिंहानंद मामले में भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप

गाजियाबाद पुलिस ने ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट शेयर करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। जुबैर पर यति नरसिंहानंद से जुड़े विवादित पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष और डासना देवी मंदिर से जुड़ी डॉक्टर उदिता त्यागी ने जुबैर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

गाजियाबाद। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष और डासना देवी मंदिर से जुड़ी डॉक्टर उदिता त्यागी की शिकायत पर अल्ट न्यूज (Alt News) से जुड़े मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) पर कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जुबैर पर यति नरसिंहानंद से जुड़े भड़काऊ पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप है। उदिता त्यागी ने आज दोपहर में पुलिस आयुक्त को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी।

मुकदमा दर्ज कराने से पहले उदिता त्यागी और महेश आहूजा सहित सात लोगों ने पुलिस आयुक्त अजय मिश्र से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त से यति को रिहा करने की मांग की गई। जिसके जवाब में आयुक्त ने कहा कि पुलिस को यति नरसिंहानंद के बारे में जानकारी नहीं है कि वो कहां हैं।

मोहम्मद जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार करने की मांग की गई है। हिंदूवादी संगठनों ने 13 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर महापंचायत की घोषणा की है।

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने प्लॉट योजना को बनाया कमाई का धंधा, उद्यमियों ने कहा- यह गंदा तरीका

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। औद्योगिक नगरी के 11 हजार उद्यमियों का आरोप है कि प्राधिकरण औद्योगिक हित की बजाय उद्यमियों से अवैध कमाई कर रहा है। दो साल से 44 औद्योगिक प्लॉट की योजना निकाली गई लेकिन प्लॉट आवंटित नहीं हुए। उल्टा उद्यमियों से 5900 रुपये प्रति ब्रोशर फीस और 60180 रुपये प्रोसेसिंग फीस फंसा कर रखी है।

नोएडा। औद्योगिक नगरी के 11 हजार उद्यमियों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहा कि प्राधिकरण औद्योगिक हित की बजाए उद्यमियों से अवैध कमाई कर रहा है। इससे उद्यमियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। दो वर्ष से 44 औद्योगिक प्लॉट की योजना को बार बार निकाला गया, लेकिन प्लॉट आवंटित नहीं हुआ।

उल्टा उद्यमियों से 5900 रुपये प्रति ब्रोशर फीस व 60180 रुपये प्रोसेसिंग फीस फंसा कर रखी है, जिसका प्रति माह 10 प्रतिशत ब्याज प्राधिकरण हड़प रहा है। जब हल्ला मचा तो ग्रेनो प्राधिकरण ने बिना सूचना योजना रद कर दी। इससे उद्यमियों को बैंक में प्रति माह 14 प्रतिशत ब्याज का दंड भुगतना पड़ रहा।

प्राधिकरण की धंधेबाजी के खिलाफ उद्यमियों ने नोएडा एंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन (एनईए) के अवगत कराया। मामले की गंभीरता देख एनईए ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश व औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री को पत्र लिखकर प्राधिकरण की रूबरू करा तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

50 हजार जमीन थी आरक्षित

एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन ने कहा 30 जनवरी को ग्रेनो प्राधिकरण ने 44 औद्योगिक प्लॉटों की योजना लॉन्च की। इसमें 50 एकड़ जमीन आवंटन के लिए आरक्षित थी। आठ प्लॉट सेक्टर ईकोटेक वन एक्सटेंशन वन में, ईकोटेक वन एक्सटेंशन में एक प्लॉट, ईकोटेक चार में एक, ईकोटेक पांच में दो, ईकोटेक छह में 22 प्लॉट, उद्योग केंद्र एक्सटेंशन वन में सात व उद्योग विहार एक्सटेंशन में दो प्लॉट प्लॉट 135 वर्ग मीटर से लेकर 20354 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के थे। तीन बार योजना की तिथि बढ़ी।

योजना की आड़ में अवैध कमाई का धंधा

हजारों उद्यमियों ने 5900 और 60180 रुपये प्राधिकरण खाते में जमा किए, 20 सितंबर को योजना रद कर दी गई। पिछले वर्ष भी यही खेल हुआ। योजना की आड़ में अवैध कमाई का धंधा शुरू हो गया है। एक तरफ प्रदेश सरकार औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है। दूसरी तरफ प्राधिकरण योजनाएं निकाल कर उद्यमियों को फार्म बेचकर एवं रजिस्ट्रेशन फीस लेकर ठगने का काम कर रही।

योजना रद के बाद राशि वापस न कर उद्यमियों का शोषण किया जा रहा। सरकार से निवेदन है कि मामले में हस्तक्षेप कर प्राधिकरण को निर्देश दे कि आवेदन करने वाले उद्यमियों का साक्षात्कार कर प्लॉट आवंटित किए जाए। नहीं करने पर उन्हें फार्म व प्रोसेसिंग फीस ब्याज सहित वापस की जाए।

अधिकतर आवेदकों का पैसा रिफंड कर दिया गया है, 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंक का आइएफएससी कोड गलत दिया था, उनके पैसे भी जल्द रिफंड होंगे। फार्म का शुल्क वापस नहीं किया जाता है। शासन स्तर से निर्णय के बाद तय होगा कि आवंटन की प्रक्रिया क्या होगी। -सौम्य श्रीवास्तव, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण।

प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते कदम

विजय गर्ग

भारत के लोगों ने पिछले कई सालों से पाश्चात्य अंधानुकरण के कारण न केवल अपने जीवन, बल्कि कृषि को भी अंधकारमय बना दिया है। इस मशीनी युग में खाद्यान्न उत्पादन लिए इस्तेमाल हो रहे रासायनिक खाद और कीटनाशकों से खाद्य सामग्री जहरीली होने लगी है। देश में कृषि को बढ़ावा देने के नाम पर काफी समय से इस्तेमाल हो रहे रसायनों के चलते धरती अब अपनी उर्वरा शक्ति भी खोने लगी है। यह हकीकत है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की कृषि संस्कृति को तबाह करने पर तुली हुई हालांकि धरती । रसायनों से मुक्ति दिलाने और देश के नागरिकों को शुद्ध खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिहाज से शून्य लागत में प्राकृतिक खेती एक बड़ा विकल्प बनकर उभर रही है। सरकार भी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। उसका मानना है कि प्राकृतिक खेती से सबसे ज्यादा फायदा देश के अस्सी फीसद छोटे किसानों को होगा। ऐसे छोटे किसान, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है। इनमें से अधिकांश किसानों का काफी खर्च रासायनिक उर्वरकों पर होता है। अगर किसान प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ेंगे तो उनकी स्थिति और बेहतर होगी।

केंद्र सरकार ने इस वर्ष के बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उसने एलान किया है कि अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को इसके लिए सहायता दी जाएगी और एक हजार 'बायो रिसर्च सेंटर' स्थापित किए जाएंगे। देश के अधिकांश कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राकृतिक खेती में लागत कम होती है, लेकिन पैदावार को लेकर अब भी किसान और

कृषि वैज्ञानिकों को संदेह है। गौरतलब है कि आज ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए कृषि क्षेत्र में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे। शहर स से लेकर गांव तक कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। नहीं है। फलतः आम जनता के साथ-साथ किसा किसानों को भी कई दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। इससे किसान का खर्च और कर्ज दोनों बढ़ रहा है, क्योंकि किसानों को रासायनिक खाद, कीटनाशक और हाइब्रीड बीज महंगे दाम पर खरीदने पड़ते हैं। कई बार किसान बैंक कर्ज के जाल में फंसने से आत्महत्या तक कर लेते हैं ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इतना नहीं, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी प्रदूषित हो रही हानिकारक कीटों की की वृद्धि हो रही है। विभिन्न प्रकार के लाभकारी जीवों जैसे- मछली, केंचुआ स दूसरे कीट-पतंगों की कमी हो रही है। रासायनिक खाद और कीटनाशक प्रभावित खानपान से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए बदलते वक्त और खेती की लागत ज्यादा होने की वजह से अब किसानों का रुख धीरे-धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है।

वर्तमान में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 13.6 फीसद है। यह क्षेत्र देश की 60 फीसद आबादी को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मुहैया कराता है। लेकिन देशभर में किसानों की वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उत्पादन और मूल्य प्राप्ति दोनों में अनिश्चितता की वजह से किसान उच्च लागत वाली कृषि के दुश्चक्र में फंस गया है। किसानों की पैदावार का आधा हिस्सा उनके उर्वरक और कीटनाशक में ही चला जाता है। इस तरह किसान आज लाचार और विवश है। वह भ्रमित है। परिस्थितियां उसे लालच की ओर धकेल रही हैं। उसे नहीं मालूम कि उसके लिए सही क्या है? अधिकतर कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि रासायनिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती में फसल की उपज कम होती है, फिर केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती के समर्थन में क्यों है। दरअसल, सरकार को प्राकृतिक खेती के जरिए खाद अनुदान, मिट्टी की घटती उर्वरा शक्ति और जल संकट जैसी चुनौतियों से निपटने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि देश के वैज्ञानिक हरित क्रांति और रसायन आधारित कृषि पर अनुसंधान करते रहे हैं और इसी के आधार पर किसान खेती करते आए हैं। उसमें अब बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि रासायनिक खाद से खेती करने से किसान और देश दोनों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक अनुमान के के मुताबिक हमारे देश में देश में पांच करोड़ रासायनिक खादों का आयात होता है, जिसके लिए अनुदान एक लाख करोड़ रुपए है। इससे दोगुने से ज्यादा पैसा बाहर के देशों को रासायनिक उर्वरकों की खरीदारी के लिए जा रहा है।

यह भी कहा जा रहा है कि प्राकृतिक खेती काफी सरल और फायदेमंद है। विशेषज्ञों के अनुसार प्राकृतिक विधि से खेती करने में किसानों को खेती करने के लिए बाहर से कोई भी । चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। खेती में सही तकनीक के उपयोग से भूमि वातावरण से फसलों में पोषक तत्त्वों की जरूरत पूरी की जा सकती है। इस विधि से खेती करने वाले किसानों को बाजार से किसी प्रकार की खाद और कीटनाशक रसायन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। फसलों की सिंचाई के लिए पानी और बिजली भी मौजूदा खेती-बाड़ी की तुलना में दस फीसद 'खर्च होती है। सबसे बड़ी बात, इससे पर्यावरण को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचता।

कहा जा सकता है कि प्राकृतिक खेती अपनाने से लागत कम हो जाती है। हमारे देश में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक आदि राज्यों में बड़े पैमाने पर किसान इस खेती को अपना चुके हैं। पंजाब में भी कई साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है। हां, एक दिक्कत जरूर है कि इस तरह की प्राकृतिक खेती वर्ष भर देखभाल मांगती है। शुरू में यह ज्यादा मेहनत भी मांगती है। लेकिन इससे गांव में रोजगार के अवसर बढ़ते है। बेरोजगारी कम होती है। पर दूर शहर में रह कर खेती कराने वाले या अंशकालिक किसानों को थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। केवल नौकरी के भरोसे प्राकृतिक खेती करने वाले के लिए उतनी अनुकूल नहीं है, जितनी वर्तमान की रासायनिक खेती।

बहरहाल, प्राकृतिक खेती छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि फिलहाल खेती के लिए रसायनों आदि की भारी कीमत चुकाने के लिए किसानों को कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज का यह बोझ बढ़ता ही रहा है। किसान रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग से न केवल कर्ज में डूब रहा है, बल्कि खेतों में जहर की खेती भी कर रहे हैं। अनाज और सब्जियों के माध्यम से यही जहर हमारे शरीर में जाता है, जिससे आज कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां लगातार फैल रही हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला किसान कर्ज के झंझट से भी मुक्त रहता है, वहीं उन्नत कृषि उत्पादों से आम जनजीवन का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है। अगर हमें अपने परिवार और समाज को स्वस्थ रखना है, तो हमें प्राकृतिक खेती की ओर लौटना होगा। यह एक बड़ा, लेकिन जरूरी काम है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर

– :सौजन्य :–

ईवी ड्राइव द फ्यूचर

EV Drive the Future

चीन की इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक एक अवसर है, खतरा नहीं - सौजन्यः चाइना मीडिया ग्रुप, बीजिंग

परिवहन विशेष न्यूज

यूरोप के लिए चीनी इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक न तो धमकी है और न ही खतरा, बल्कि विकास का अवसर है। हंगरी के अर्थव्यवस्था मंत्री मार्टन नेगी ने हाल ही में चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में यह बात कही।

चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर यूरोपीय संघ द्वारा अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के मुद्दे पर मार्टन नेगी ने कहा कि यह सबसे खराब तरीका है, जो पूरी मानव जाति और वैश्विक विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देगा। उनकी राय में दंडात्मक शुल्क लगाने की तुलना में चीन के साथ सहयोग करना बेहतर समाधान है।

उन्होंने आगे कहा कि अतिरिक्त शुल्क लगाना आर्थिक दृष्टिकोण से आधारित नहीं है, बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। यह आर्थिक रूप से अनुचित है और दुनिया के समग्र विकास को कमजोर करेगा। उनका मानना है कि संवाद और सहयोग ही सबसे अच्छा समाधान है।

मार्टन नेगी की राय में यूरोपीय और अमेरिकी देशों को अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उन्हें आगे और व्यापक प्रयास करने चाहिए। उनका कहना है कि यूरोपीय और अमेरिकी देशों को अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश करके चीन के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है। यह सभी पक्षों के लिए फायदेमंद है।

इसके अलावा मार्टन नेगी ने कहा कि चीन की इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक बहुत उन्नत है। उन्होंने पहले भी चीन का दौरा किया था, तब भी उन्हें इसका अनुभव हुआ था। उनका मानना है कि चीनी इलेक्ट्रिक वाहन अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत प्रतिस्पर्धी हैं।

किआ भारत में लॉन्च करेगी नई इलेक्ट्रिक कार

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक कारों की लोकप्रियता को देखते हुए किआ इंडिया इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि वह साल 2030 तक भारत में 4 लाख यूनिट्स की वार्षिक बिक्री हासिल करे। इस योजना के तहत किआ इंडिया 2025 की पहली छमाही में एक नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है, जो किआ कैरेंस ईवी हो सकती है।

किआ कैरेंस ईवी की लॉन्चिंग अगले साल यानी 2025 की दूसरी छमाही में होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह कार एक बार चार्ज होने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज प्रदान कर सकती है। इसके अलावा किआ कैरेंस ईवी में पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, और 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करेगा।

सेफ्टी के लिहाज से किआ कैरेंस ईवी में 6-एयरबैग और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल की जाएंगी। इसके अलावा कार में पैनोरमिक सनरूफ भी होगा, जो इसे एक प्रीमियम टच देगा।

किआ इंडिया एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी भी विकसित कर रही है, जिसका नाम किआ साइरोस रखा जा सकता है। यह एसयूवी कंपनी के लाइनअप में सोनेट से ऊपर प्लेस की जाएगी और उन ग्राहकों को टारगेट करेगी, जो सोनेट से थोड़ा बड़ा और अधिक प्रीमियम विकल्प चाहते हैं।

किआ कैरेंस ईवी और किआ साइरोस जैसे नए मॉडल्स से उम्मीद की जा रही है कि ये किआ की भारतीय बाजार में पकड़ को और मजबूत करेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में उनकी स्थिति को और बेहतर बनाएंगे।

केके पॉल ने टीआई क्लीन मोबिलिटी के एमडी पद से दिया इस्तीफा

परिवहन विशेष न्यूज

टीआई क्लीन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कल्याण कुमार पॉल ने कंपनी से अपने इस्तीफे की घोषणा की है, जिसके साथ ही ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया (टीआईआई) समूह के साथ उनके 30 साल के सफर का अंत हो गया है। टीआईआई समूह के साथ पॉल के करियर में कई प्रमुख नेतृत्वकारी भूमिकाएँ शामिल हैं, जिसमें टीआई साइकिल्स ऑफ इंडिया और ट्यूब प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया में उनके सफल कार्यकाल शामिल हैं, जो टीआईआई के अंतर्गत आने वाली दोनों मुख्य व्यावसायिक इकाइयाँ हैं। पॉल को टर्नअराउंड विशेषज्ञ के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है, उन्होंने व्यवसायों को सफलता की ओर ले जाने के लिए प्रतिष्ठा बनाई है। उन्होंने अपना करियर एक पेशेवर सेवा प्रतिनिधि के रूप में शुरू किया, और उनकी विशेषज्ञता स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल्स, शॉ वालेस, सीएट और जेके टायर जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ उनके काम के माध्यम से कई क्षेत्रों में फैली।

पॉल ने प्रेसीडेंसी कॉलेज, कोलकाता से विज्ञान स्नातक की डिग्री तथा भारतीय समाज कल्याण एवं व्यवसाय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता से बिक्री एवं विपणन में एमबीए की डिग्री प्राप्त की है।

टाटा मोटर्स फाइनेंस और बैंक ऑफ इंडिया ने वाणिज्यिक वाहनों के वित्तपोषण के लिए सह-स्रोत समझौते पर किए हस्ताक्षर

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा मोटर्स फाइनेंस और बैंक ऑफ इंडिया ने वाणिज्यिक वाहनों के लिए वित्तपोषण की सुलभता बढ़ाने के लिए सह-स्रोत समझौता किया है।

इस समझौते का उद्देश्य पूरे देश में वाणिज्यिक वाहन मालिकों और बेड़े संचालकों के लिए वित्तपोषण की सुलभता को बढ़ाना है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सह-स्रोत व्यवस्था दोनों संस्थाओं की ताकत का लाभ उठाएगी, जिससे सभी वाणिज्यिक वाहन खंडों के अंतिम छोर के उपयोगकर्ताओं को अधिक कुशल और विश्वसनीय ग्राहक अनुभव की सुविधा मिलेगी।

बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक अशोक कुमार पाठक ने कहा, "बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को अनुकूलित और लक्षित वित्तीय पेशकशों के साथ समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। टीएमएफ के व्यापक ऑन-ग्राउंड नेटवर्क और दशकों से मजबूत बाजार उपस्थिति का लाभ उठाकर, हम अपनी अंतिम-मील पहुंच का और विस्तार करने के बारे में आश्वस्त हैं।"

टाटा मोटर्स फाइनेंस के प्रबंध निदेशक (नामित) नीरज धवन ने कहा, "वाणिज्यिक वाहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की पूंजी-गहन प्रकृति को देखते हुए, हमारी सहयोगी ताकत इस क्षेत्र की विविध, आवर्ती वित्तपोषण आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक संबोधित करने और पूरा करने के लिए कई रास्ते खोलती है।"

महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की पिंक ई-रिक्शा योजना, सीएम एकनाथ शिंदे ने किया शुभारंभ

परिवहन विशेष न्यूज

महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की है। रविवार, 06 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने छत्रपति संभाजीनगर में इस योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से महाराष्ट्र में पात्र महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजन से राज्य भर के 17 शहरों की करीब 10,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा ।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पूर्व योजना शुरू करने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार, 06 अक्टूबर को कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है। नवरात्र चल रहे हैं। मैंने लाडली बहन योजना शुरू की। 2.5 करोड़ मेरी लाडली बहनों को इसका फायदा मिला है। आज पिंक रिक्शा योजना भी यहां पर शुरू हुई है। आज हमारी कई बहनों को पिंक रिक्शा दी गई है।

सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की थी, जिसमें 20 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता देने का वादा किया गया था। पिंक ई-रिक्शा योजना की शुरुआत इसी प्रतिबद्धता पर आधारित है, जिसमें ई-रिक्शा खरीदने के लिए 80,000 रुपये तक की पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

पात्रता मानदंडों में महाराष्ट्र में स्थायी निवास और वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना शामिल है। इस योजना में न केवल लाभार्थियों को 20 प्रतिशत का योगदान देना होता है, बल्कि बैंक ऋण के माध्यम से 70 प्रतिशत धन की व्यवस्था भी की जाती है, जबकि शेष राशि सरकार वहन करती है।

मैजेंटा मोबिलिटी ने जयपुर में 'पिंक टर्न्स ग्रीन' पहल के साथ टिकाऊ परिचालन का किया विस्तार

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधान प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी मैजेंटा मोबिलिटी ने जयपुर, राजस्थान में अपने परिचालन की शुरुआत की घोषणा की है। शुरुआती चरण में, कंपनी की योजना शहर में 200 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) तैनात करने की है, जिसका लक्ष्य दिसंबर 2024 तक बेड़े को 300 ईवी तक बढ़ाना है।

इलेक्ट्रिक वाहन लॉजिस्टिक्स बाजार में अपनी बढ़ती भूमिका के लिए पहचाने जाने वाले जयपुर में मैजेंटा के विस्तार के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि इसकी रणनीतिक महत्ता और पर्यावरण के अनुकूल डिलीवरी समाधानों की बढ़ती मांग है। शहर में ई-कॉमर्स, फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में ईवी अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

इस लॉन्च में जयपुर में JITO इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन (JITO JIIF) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विस्तार के हिस्से के रूप में, मैजेंटा 100 ईवी की पार्किंग क्षमता वाला एक नया हब-एंड-स्पोक डिपो स्थापित करेगा, जिसे इसके इन-हाउस विकसित 3.3 kW पेंटा चार्जर द्वारा समर्थित किया जाएगा। कंपनी परिचालन का प्रबंधन करने के लिए 200 से अधिक स्थानीय डिलीवरी अधिकारियों की भर्ती करने की भी योजना बना रही है। शैडोफ़ैक्स, डीमार्ट, पोर्टर, गैराज और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी के माध्यम से, मैजेंटा का लक्ष्य जयपुर में मिड- और लास्ट-माइल डिलीवरी सेवाओं को बढ़ाना है।

मैजेंटा मोबिलिटी के संस्थापक और सीईओ मैक्ससन लुईस ने जयपुर में कंपनी के प्रवेश के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के माध्यम से शहरी लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि जयपुर मैजेंटा की विकास रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

वर्तमान में, मैजेंटा दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई सहित 18 शहरों में 2,500 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का परिचालन करती है, जिससे प्रतिदिन 100,000 से अधिक डिलीवरी होती है और 905 टन CO2 उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान मिलता है।

टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक वाहन 30% तक हो सकते हैं सस्ते, कंपनी बना रही है शानदार प्लान, किराए पर देगी बैटरी

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा मोटर्स अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया जबरदस्त प्लान लाने की तैयारी कर रही है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी अपने कुछ इलेक्ट्रिक मॉडल में बैटरी रेंटल की सुविधा देने पर विचार कर रही है। इस बिजनेस मॉडल को 'बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS)' कहा जाता है। कंपनी को उम्मीद है कि इस मॉडल के जरिए वह बाजार में अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर सकती है। उम्मीद है कि इसे टियागो, पंच, टिगोर, नेक्सन और अन्य मॉडल के इलेक्ट्रिक वर्जन में पेश किया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि बैटरी रेंटल की सुविधा से उपभोक्ताओं के लिए वाहन की एक्स-शोरूम कीमत 25 से 30 फीसदी तक कम हो जाएगी। BaaS मॉडल में कार खरीदार बिना बैटरी वाला इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, जिससे ईवी की शुरुआती कीमत कम हो जाती है। बदले में ग्राहकों को प्रति किलोमीटर के हिसाब से बैटरी के इस्तेमाल पर किराया देना होता है।

एक सूत्र ने कहा, इस बात की पूरी संभावना है कि टाटा मोटर्स BaaS सुविधा प्रदान करेगी, क्योंकि ग्राहक किफायती ईवी विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। संभावित ग्राहक मासिक आधार पर बैटरी का किराया देने को तैयार हैं, जिससे कार चलाना किफायती हो जाता है। हालांकि, सूत्र ने स्पष्ट किया कि योजना अभी भी ड्राइंग बोर्ड पर है और कोई भी अंतिम निर्णय पायलट रन के बाद ही लिया जाएगा।

घरेलू यात्री वाहन बाजार में, इस तरह की योजना सबसे पहले JSW MG मोटर इंडिया ने विंडसर ईवी में पेश की थी, जिसकी कीमत 13,49,800 रुपये से 15,49,800 रुपये के बीच है। इसे BaaS सुविधा (3.50 रुपये/किमी) के साथ 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में खरीदा जा सकता है। बाद में, कंपनी ने कॉमेट ईवी (कीमत 4.99 लाख रुपये से शुरू होती है + बैटरी किराया 2.5 रुपये/किमी) और जेडएस ईवी (कीमत 13.99 लाख रुपये से शुरू होती है + बैटरी किराया 4.5 रुपये/किमी) में यह सुविधा देना शुरू किया।

टाटा मोटर्स अपने EV मॉडल जैसे टियागो ईवी (7.99 लाख रुपये से शुरू), टिगोर ईवी (12.49 लाख रुपये से शुरू), पंच ईवी (9.99 लाख रुपये से शुरू), नेक्सन ईवी (12.49 लाख रुपये से शुरू) के इलेक्ट्रिक वेरिएंट बेच रही है। इसके अलावा इसने हाल ही में कर्व ईवी (17.49 लाख रुपये से शुरू) लॉन्च किया है। इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक BaaS स्कीम इन मॉडलों की कीमतों में 2-3.5 लाख रुपये (बैटरी को छोड़कर) की कमी कर सकती है।

आईबी, सीबीएसई या आईसीएसई - कौन सा स्कूल बोर्ड आपके बच्चे के भविष्य को बेहतर ढंग से आकार दे सकता है और उनमें से कैसे चुनें?

आईबी स्कूल स्थित प्रिंसिपल ने इस बात पर जोर दिया कि आईबी एक पूछताछ-आधारित पद्धति पर ध्यान केंद्रित करती है जो छात्रों को केवल तथ्यों को याद रखने के बजाय अवधारणाओं के साथ गंभीर रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह दृष्टिकोण रचनात्मकता, मूल्यांकन और सहयोग जैसे महत्वपूर्ण कौशल को बढ़ावा देता है, जिनकी दुनिया भर में नियोक्ताओं द्वारा अत्यधिक मांग की जाती है। "आईबी की जांच-आधारित पद्धति तथ्यों को दोबारा पेश करने के बजाय अवधारणाओं को समझने और जोड़ने पर केंद्रित है।

विजय गर्ग

आईबी एक व्यापक, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त शिक्षा प्रदान करता है, सीबीएसई एक ठोस शैक्षणिक आधार प्रदान करता है और आईसीएसई रचनात्मकता और विश्लेषणात्मक सोच का पोषण करता है। आईबी, सीबीएसई या आईसीएसई - कौन सा स्कूल बोर्ड आपके बच्चे के भविष्य को बेहतर ढंग से आकार दे सकता है और उनमें से कैसे चुनें? आईबी का पूछताछ-आधारित मॉडल महत्वपूर्ण सोच और वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देता है, जबकि सीबीएसई का संरचित दृष्टिकोण छात्रों को पारंपरिक शैक्षणिक मार्गों के लिए तैयार करता है। (छविः गेटी) अपने बच्चे के लिए सही शैक्षिक बोर्ड का चयन करना एक महत्वपूर्ण उपक्रम है जिसमें सावधानीपूर्वक विचार करना शामिल है। भारत में, माता-पिता आम तौर पर तीन प्रमुख विकल्पों पर विचार करते हैंः अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्नातक (आईबी), सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड), और आईसीएसई (भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र)। प्रत्येक बोर्ड विविध छात्र आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए अद्वितीय शैक्षिक दर्शन, शिक्षण विधियों और दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। आइए इन बोर्डों के प्रत्येक पहलू की खोज करें- अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्नातक (आईबी) 1968 में जिनेवा में स्थापित, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (आईबी) भारतीय परिवारों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गया है। वर्तमान में, भारत में लगभग 210 आईबी वर्ल्ड स्कूल हैं, जो मुख्य रूप से नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बैंगलोर जैसे प्रमुख शहरों में स्थित हैं। यह वृद्धि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त शिक्षा की बढ़ती मांग को इंगित करती है जो छात्रों को एक जुड़ी हुई दुनिया के लिए तैयार करती है। आईबी स्कूल स्थित प्रिंसिपल ने इस बात पर जोर दिया कि आईबी एक पूछताछ-आधारित पद्धति पर ध्यान केंद्रित करती है जो छात्रों को केवल तथ्यों को याद रखने के बजाय अवधारणाओं के साथ गंभीर रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह दृष्टिकोण रचनात्मकता, मूल्यांकन और सहयोग जैसे महत्वपूर्ण कौशल को बढ़ावा देता है, जिनकी दुनिया भर में नियोक्ताओं द्वारा अत्यधिक मांग की जाती है। "आईबी की जांच-आधारित पद्धति तथ्यों को दोबारा पेश करने के बजाय अवधारणाओं को समझने और जोड़ने पर केंद्रित है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियोक्ता ऊपर बताए गए कई कारणों से आईबी का समर्थन करते हैं, लेकिन अंततः पाठ्यक्रम की परवाह किए बिना, सभी नियोक्ता उद्यमशीलता की मानसिकता, संक्रामक ऊर्जा, सहयोग करने की इच्छा और दुनिया में जहां भी रहें वहां पनपने की इच्छा वाले युवाओं की तलाश करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 1929 में स्थापित, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) भारत सरकार के तत्वावधान में संचालित होता है और यह देश के सबसे मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्डों में से एक बन गया है। भारत में 24,000 से अधिक संबद्ध स्कूलों और विदेशों में लगभग 240 स्कूलों के साथ, सीबीएसई का व्यापक नेटवर्क इसे कई परिवारों के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बनाता है। सीबीएसई पाठ्यक्रम गणित,

विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे मुख्य विषयों पर जोर देता है, जो इंजीनियरिंग या चिकित्सा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रवेश करने के इच्छुक छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, मानकीकृत परीक्षण पर बोर्ड का ध्यान छात्रों को जेईई और एनईईटी सहित राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। नई दिल्ली के प्रिंसिपल का मानना है कि सीबीएसई पाठ्यक्रम छात्रों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने, उन्हें प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने पर केंद्रित है। कई माता-पिता आईबी को विश्व स्तर पर जागरूक व्यक्तियों को विकसित करने की क्षमता के कारण पसंद करते हैं। अंततः, सीबीएसई और आईबी के बीच चयन इस बात पर निर्भर करता है कि माता-पिता राष्ट्रीय परीक्षा तैयारी या वैश्विक तैयारी को प्राथमिकता देते हैं या नहीं। "सीबीएसई द्वारा नियोजित मूल्यांकन तकनीक समग्र विकास, रचनात्मकता और विश्लेषणात्मक कौशल को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। बोर्ड की प्रतिबद्धताछात्र-केंद्रित शिक्षण माहौल को बढ़ावा देने से इसके छात्र भारत में विश्वविद्यालयों और नियोक्ताओं के लिए आकर्षक बनते हैं।" भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (आईसीएसई) 1958 में स्थापित, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (आईसीएसई) अपने व्यापक और कठोर पाठ्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है, जो शिक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। भारत भर में लगभग 2,500 संबद्ध स्कूलों के साथ, मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में, आईसीएसई शैक्षिक अनुभव चाहने वाले परिवारों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है जो रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। आईसीएसई पाठ्यक्रम में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो छात्रों को अपनी पढ़ाई के साथ गहराई से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें प्रोजेक्ट कार्य, व्यावहारिक मूल्यांकन और भाषाओं पर ज़ोर दिया गया है, जो इसे विभिन्न रुचियों वाले छात्रों, विशेषकर कला और मानविकी में, के लिए उपयुक्त बनाता है। स्कूल, मुंबई के प्रिंसिपल ने इस बात पर जोर दिया कि, आईसीएसई का शिक्षण दृष्टिकोण परियोजना-आधारित असाइनमेंट, व्यावहारिक अनुप्रयोगों और अनुभवात्मक शिक्षा को प्राथमिकता देता है, जो छात्रों को पाठ्यपुस्तकों से परे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सैद्धांतिक शिक्षा और परीक्षा की तैयारी पर सीबीएसई के जोर के विपरीत है। "आईसीएसई छात्रों को अक्सर संपन्न व्यक्ति माना जाता है। जहां पाठ्यक्रम संरेखण के कारण सीबीएसई स्नातकों को भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पसंद किया जाता है, वहीं आईसीएसई छात्रों को उनकी व्यापक शिक्षा और मजबूत भाषा दक्षता के कारण भारतीय और वैश्विक विश्वविद्यालयों दोनों के लिए बेहतर रूप से तैयार माना जाता है। नियोक्ता आईसीएसई स्नातकों को उनकी विश्लेषणात्मक क्षमताओं, टीम वर्क कौशल और प्रभावी संचार के लिए भी महत्व देते हैं।" मुख्य अंतर और विकास प्रक्षेपवक्र चूंकि माता-पिता इन शैक्षिक विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं, इसलिए शिक्षण पद्धतियों और पाठ्यक्रम फोकस में अंतर को समझना आवश्यक है। आईबी का पूछताछ-आधारित मॉडल महत्वपूर्ण सोच और वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देता है, जबकि सीबीएसई का संरचित दृष्टिकोण छात्रों को पारंपरिक शैक्षणिक मार्गों के लिए तैयार करता है। दूसरी ओर, आईसीएसई उन लोगों के लिए गहराई और रचनात्मकता पर जोर देता है जो अधिक विविध शैक्षिक वातावरण में फलते-फूलते हैं। आईबीः अंतरराष्ट्रीय शिक्षा की बढ़ती मांग के कारण हाल के वर्षों में आईबी में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। अधिक परिवार आईबी डिप्लोमा के मूल्य को पहचान रहे हैं, जो दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के बीच सम्मान रखता है। सीबीएसईः सीबीएसई ने भारत में सबसे बड़े शैक्षिक बोर्ड के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है, जो लगातार अपने पाठ्यक्रम को विकसित शैक्षिक परिदृश्य के अनुरूप ढाल रहा है। स्कूलों का इसका विशाल नेटवर्क इसे देश भर के परिवारों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाता है। आईसीएसईः हालांकि आईसीएसई पैमाने में छोटा है, लेकिन समग्र शिक्षा और आलोचनात्मक सोच के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण नामांकन में लगातार वृद्धि का अनुभव हुआ है, जो विशेष रूप से समृद्ध शैक्षिक अनुभव की तलाश में शहरी परिवारों को आकर्षित करता है। अंततः, आईबी, सीबीएसई और आईसीएसई के बीच चयन आपके बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं, रुचियों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। जबकि आईबी एक व्यापक, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त शिक्षा प्रदान करता है, सीबीएसई एक ठोस शैक्षणिक आधार प्रदान करता है और आईसीएसई रचनात्मकता और विश्लेषणात्मक सोच का पोषण करता है। इन विकल्पों की खोज करके, माता-पिता सूचित निर्णय ले सकते हैं जो उनके बच्चे की शैक्षिक यात्रा का सर्वोत्तम समर्थन करते हैं, उनके लक्ष्यों और सपनों के अनुरूप मार्ग सुनिश्चित करते हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चांद एमएचआर

सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की चुनौतियां : विजय गर्ग

देश में तेज आर्थिक विकास के साथ जैसे-जैसे असंगठित और अनुबंध आधारित रोजगार का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की चिंताएं तेजी से बढ़ रही हैं। सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा का संबंध ऐसी कानूनी व्यवस्था से है, जिसके तहत व्यक्ति या परिवार की आय के कुछ या सभी स्रोत बाधित हो जाएं, तब संबंधित व्यक्ति या परिवार का उपयुक्त रूप से ध्यान रखा जा सके। सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के तहत जीवन चक्र में सामना किए जाने वाले बेरोजगारी भत्ता, विकलांगता लाभ, छंटनी लाभ, स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा लाभ, मातृत्व अवकाश आदि लाभ प्रदान किए जाते हैं। निश्चित रूप से सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा मानव पूंजी निर्माण में या तो सीधे भोजन, कौशल और सेवाएं प्रदान करके योगदान देती है, या परोक्ष रूप से नकदी पहुंच प्रदान करके परिवारों को उनके विकास में सक्षम बनाती है। भारत सरकार द्वारा नागरिकों की सामाजिक भलाई सुनिश्चित करने और उन्हें विविध माध्यमों से आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के मद्देनजर निशुल्क आवास, खाद्य सुरक्षा, सबसिडी वाली रसोई गैस, जन-धन योजना के माध्यम से गरीबों और किसानों को निर्धारित धनराशियां देकर करोड़ों लोगों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आइएलओ की रपट के मुताबिक दुनिया में महज 140 देशों में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं हैं। दुनिया के विकासशील देशों में खासकर ये योजनाएं श्रमिकों की बीमारी, विकलांगता, बेरोजगारी पेंशन आदि से संबंधित हैं। हालांकि भारत सरकार विभिन्न माध्यमों से सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा का दायरा विस्तृत करने की डगर पर लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी देश के अधिकांश लोग सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की उपयुक्त छतरी से दूर हैं। देश के ऐसे करोड़ों लोग, जो अपनी बचत से अपनी सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध करते हैं, वे बैंकों की 'फिक्सड डिपाजिट तथा डाकखाने और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी विभिन्न बचत योजनाओं पर मिलने वाली कम ब्याज दरों से चिंतित हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 11 सितंबर को सत्तर वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वर्गों के लोगों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इससे 4.5 करोड़ परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है। इन परिवारों में छह करोड़ बुजुर्ग हैं। इसी तरह केंद्र सरकार ने अगस्त में सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी है।

निश्चित रूप से अभी देश का आम आदमी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए चिंतित रहता है। देश के करीब 57 करोड़ के श्रमबल में से तीन फीसद से भी कम सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी

यूपीएस से जुड़े हुए हैं। मगर करोड़ों श्रमिकों और कर्मचारियों से संबंधित संगठित निजी क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के श्रमबल के सामने वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों के अलावा संगठित निजी क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी पेंशन की कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वे वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर अपर्याप्त और असंतोषप्रद हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मात्र 436 रुपए वार्षिक भुगतान पर दो लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। यह योजना 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष के लोग बीस रुपए वार्षिक भुगतान पर दो लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। इसके तहत साठ वर्ष की उम्र में एक हजार रुपए से लेकर पांच हजार रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दी जाती है। देश का कोई भी श्रमिक जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच हो, एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है।

इसी तरह व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने दो प्रमुख पेंशन योजनाएं शुरू की हैं- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान- धन योजना (पीएम-एसवाईएम) और व्यापारियों, दुकानदारों तथा स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस-ट्रेडर्स)। इन योजनाओं के तहत, लाभार्थी साठ वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम तीन हजार रुपए की मासिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि 18-40 वर्ष की आयु के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय पंद्रह हजार रुपए से कम है, वे पीएम एसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं और व्यापारी, दुकानदार और स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति, जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वे एनपीएस- ट्रेडर्स योजना में शामिल हो सकते हैं। दोनों योजनाओं के तहत लाभार्थी द्वारा 50 फीसद मासिक अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा समान मिलान अंशदान का भुगतान किया जाता है।

संगठित क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सबसे बड़ा सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा संगठन है। भविष्य निधि के लिए कर्मचारी का जो अशंदान करता है, उसका एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएफ) में जाता है। पेंशन के लिए शर्त है कि कर्मचारी को कम से कम दस वर्ष तक नौकरी करनी होती और पीएफ खाते में अंशदान करना होता है। मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा पंद्रह हजार रुपए है। ईपीएफ सदस्य को न्यूनतम एक हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन मिल पाती है। इसे साढ़े सात हजार रुपए प्रति माह करने की मांग लंबे समय से हो रही है। असंगठित क्षेत्र के श्रमबल द्वारा सरकार के समक्ष उपयुक्त पेंशन की मांग की जा रही है। इसमें कोई दो मत नहीं कि इस समय 'गिग वर्क' सहित नई निर्मित नौकरियों में से ज्यादातर नौकरियां असंगठित क्षेत्र में सृजित हो रही हैं और इनमें पेंशन संबंधी सुरक्षा नहीं है। 'गिग' अर्थव्यवस्था का मतलब है अनुबंध आधारित या अस्थायी रोजगार वाली अर्थव्यवस्था।

एक चिंताजनक प्रश्न यह भी है कि जहां असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोग पेंशन व्यवस्था से दूर हैं, वहीं बचत पर घटी हुई ब्याज दर और विभिन्न आकर्षण कम होने के कारण देश में सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की चिंताएं बढ़ रही हैं। अभी भी देश में बड़ी संख्या में लोगों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की छतरी उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों पर देश के उन तमाम छोटे निवेशकों का दूरगामी आर्थिक प्रबंधन निर्भर होता है, जो अपनी छोटी बचतों के जरिए जिंदगी के कई महत्त्वपूर्ण कामों को निपटाने की व्यवस्था सोचे हुए हैं। ऐसे में उपयुक्त पेंशन की अहमियत है। अब सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना होगा कि वह निजी क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्रों में सेवा देने वाले करोड़ों लोगों के लिए उपयुक्त सम्मानजनक पेंशन और सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के बारे में गंभीरतापूर्वक ध्यान दे और निजी क्षेत्र की पेंशन योजनाओं को भी आकर्षक बनाए।

हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव

विजय गर्ग

सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हम इसका उपयोग दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहने, अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने और अपने आस-पास की दुनिया के बारे में जानने के लिए करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस बात के कुछ सबूत हैं कि सोशल मीडिया मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए, अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करते हैं उनमें अवसाद, चिंता और अकेलेपन के लक्षणों का अनुभव होने की संभावना अधिक होती है। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया जीवन के बारे में अवास्तविक अपेक्षाओं को जन्म दे सकता है, जिससे लोग अपने जीवन में अपर्याप्त या नाखुश महसूस कर सकते हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य पर सभी शोधों में नकारात्मक परिणाम नहीं मिले हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि सोशल मीडिया वास्तव में सामाजिक समर्थन के लिए एक मंच प्रदान करके और लोगों को उनके हितों को साझा करने वाले अन्य लोगों से जोड़कर मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अंततः, सोशल मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध जटिल है। संभावित नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव हैं, और किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव संभवतः कई कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि उनका व्यक्तित्व, सोशल मीडिया का उपयोग और उनका समग्र मानसिक स्वास्थ्य। नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण से, मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के संभावित नकारात्मक प्रभावों के प्रति सचेत रहना महत्वपूर्ण है। हमें अवास्तविक अपेक्षाओं, सामाजिक तुलना और साइबरबुलिंग के जोखिमों से अवगत होना चाहिए और हमें इन जोखिमों को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। उदाहरण के लिए, हम सोशल मीडिया पर उपभोग की जाने वाली सामग्री के बारे में चयनात्मक हो सकते हैं, और हम सोशल मीडिया पर बिताए गए अपने समय को सीमित कर सकते हैं। हमें मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के संभावित सकारात्मक प्रभावों के बारे में भी जागरूक होना चाहिए। सोशल मीडिया सामाजिक समर्थन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, और यह हमें उन लोगों से जुड़ने में मदद कर सकता है जो हमारे हितों को साझा करते हैं। हम रिश्ते बनाने, संसाधन खोजने और खुद को अभिव्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। रीलों की पीढ़ी! सबसे बड़ी चिंताओं में से एक यह है कि रीलें अवास्तविक सौंदर्य मानकों को बढ़ावा देती हैं। उपयोगकर्ताओं पर लगातार उत्तम शरीर, बेदाग त्वचा और ग्लैमरस जीवनशैली की तस्वीरें आती रहती हैं। इससे अपर्याप्तता और कम आत्मसम्मान की भावनाएं पैदा हो सकती हैं, खासकर युवा लोगों में जो अभी भी अपने बारे में भावना विकसित कर रहे हैं। रील्स और बॉडी इमेज रीलों के बारे में सबसे आम चिंताओं में से एक यह है कि वे नकारात्मक शारीरिक छवि संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रीलों में अक्सर अत्यधिक संपादित और फ़िल्टर किए गए वीडियो होते हैं, जो सुंदर होने के अर्थ के बारे में अवास्तविक उम्मीदें पैदा कर सकते हैं। पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि जो युवा महिलाएं रील्स का उपयोग करती हैं, उनमें उन लोगों की तुलना में शरीर की छवि संबंधी

चिंताएं होने की अधिक संभावना होती है, जो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करती हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि रील्स का उपयोग चिंता और अवसाद के बढ़े हुए स्तर से जुड़ा था। रीलों और तुलना रीलों के बारे में एक और चिंता यह है कि वे तुलना की भावना पैदा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रील्स में अक्सर ऐसे लोगों के वीडियो दिखाए जाते हैं जो आदर्श जीवन जीते प्रतीत होते हैं। इससे लोगों के लिए अपने जीवन को काफी अच्छा देखना कठिन हो सकता है। कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स के एक अध्ययन में पाया गया कि जो युवा रील्स का उपयोग करते हैं, उनमें उन लोगों की तुलना में दूसरों से ईर्ष्या महसूस करने की अधिक संभावना होती है जो प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग नहीं करते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि रीलों का उपयोग सामाजिक स्तर में वृद्धि से जुड़ा थाचिंता। रील्स और लत अंत में, एक चिंता यह भी है कि रीलों की लत लग सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रीलों को अत्यधिक आकर्षक बनाने और उपयोगकर्ताओं को बांधे रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। परिणामस्वरूप, बिना एहसास हुए भी रीलों को स्क्रॉल करते हुए घंटों बिताना आसान हो सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो युवा रील्स का उपयोग करते हैं, उनमें सोशल मीडिया के आदी होने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक होती है, जो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि रील्स का उपयोग तनाव और चिंता के बढ़ते स्तर से जुड़ा था। मुख्य बात सोशल मीडिया का स्वस्थ तरीके से उपयोग करना है। हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, और हमें सोशल मीडिया के संभावित नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। हमें सोशल मीडिया के संभावित सकारात्मक प्रभावों के बारे में भी जागरूक होना चाहिए और इसका उपयोग दूसरों से जुड़ने और स्वस्थ संबंध बनाने के लिए करना चाहिए। सोशल मीडिया का स्वस्थ तरीके से उपयोग करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैंः आपके द्वारा उपभोग की जाने वाली सामग्री के बारे में चयनात्मक रहें। ऐसे लोगों या खातों का अनुसरण न करें जो आपको अपने बारे में बुरा महसूस कराते हैं। एल्गोरिदम से अवगत रहें. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आपको व्यस्त रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, इसलिए वे आपको ऐसी सामग्री दिखा सकते हैं जो नकारात्मक भावनाओं को ट्रिगर करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके प्रति सचेत रहें और इससे बचने के लिए कदम उठाएं। सोशल मीडिया पर बिताए गए अपने समय को सीमित करें। प्रतिदिन 30 मिनट या उससे कम समय बिताने का लक्ष्य रखें। सोशल मीडिया से ब्रेक लें. अपना फ़ोन दूर रखें और वास्तविक जीवन में लोगों के साथ समय बिताएँ। कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहें, खासकर यदि आप चिंतित या उदास महसूस कर रहे हों। किसी से बात करो. यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं, तो किसी विश्वसनीय मित्र, परिवार के सदस्य या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं. ऐसे लाखों लोग हैं जो सोशल मीडिया के बारे में आपकी तरह ही सोचते हैं। सहयोगी लोगों का एक समुदाय ढूंढें जो आपको ऊपर उठाएगा, और ज़रूरत पड़ने पर मदद के लिए पहुंचने से न डरें। सकारात्मक पर ध्यान दें. जब आप उदास महसूस कर रहे हों, तो अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं, या ऐसी गतिविधियाँ जो आपको खुश करती हैं। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहें। यदि आप सोशल मीडिया का उपयोग करने के बाद उदास या चिंतित महसूस करने लगते हैं, तो ब्रेक लें। सोशल मीडिया के बिना सामाजिक बनने का प्रयास करें! दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। सामाजिक बने रहने का यह सबसे स्पष्ट तरीका है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण में से एक भी है। जिन लोगों की आप परवाह करते हैं उनके लिए समय निकालें और संपर्क में रहने के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर न रहें। किसी क्लब या समूह में शामिल हों. लगभग हर चीज़ के लिए क्लब और समूह हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से वह खोज लेंगे जिसमें आपकी रुचि हो। यह नए लोगों से मिलने और दोस्त बनाने का एक शानदार तरीका है। अपना समय स्वेच्छा से दें। स्वयंसेवा अपने समुदाय को वापस लौटाने और साथ ही नए लोगों से मिलने का एक शानदार तरीका है। कई अलग-अलग स्वयंसेवी अवसर उपलब्ध हैं, इसलिए आप कुछ ऐसा पा सकते हैं जो आपकी रुचियों और कार्यक्रम के अनुकूल हो। आयोजनों में भाग लें. आपके समुदाय में हमेशा घटनाएं घटती रहती हैं, इसलिए वहां जाएं और अन्वेषण करें! यह नए लोगों से मिलने और मौज-मस्ती करने का एक शानदार तरीका है। जिस व्यक्ति से आप नियमित रूप से मिलते हैं, उसके साथ बातचीत शुरू करें। यदि आप किराने की दुकान, लाइब्रेरी या पार्क में किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे आप पहचानते हैं, तो बातचीत शुरू करने से न डरें। आप कभी नहीं जानते कि यह कहां ले जा सकता है। सक्रिय होना। लोगों के आपके पास आने का इंतज़ार न करें. संपर्क करने और योजनाएँ बनाने वाले व्यक्ति बनें। दोस्तों को रात के खाने के लिए आमंत्रित करें, किसी संगीत समारोह में जाएँ, या साथ में सैर पर जाएँ। सकारात्मक रहो। जब आप बाहर हों तो मिलनसार और मिलनसार बनें। लोगों को देखकर मुस्कुराएँ, आँख मिलाएँ, औरडी नमस्ते कहो. यदि आप सकारात्मक और मिलनसार हैं तो लोग आपसे बात करना चाहेंगे। अंत में, अपने और दूसरों के प्रति दयालु बनें। सोशल मीडिया नकारात्मकता का प्रजनन स्थल हो सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। दयालुता और सकारात्मकता फैलाना चुनें, और आप दुनिया को एक बेहतर जगह बना देंगे। आपका मूल्य किसी पोस्ट पर मिलने वाले लाइक की संख्या या आपके फ़ॉलोअर्स की संख्या से निर्धारित नहीं होता है। सोशल मीडिया चाहे कुछ भी कहे, आप सुंदर, मूल्यवान और प्यार के योग्य हैं। हम सभी इंसान सुंदर हैं। हम सभी आकार, आकार, रंग और क्षमताओं में आते हैं। हमारी पृष्ठभूमि, अनुभव और मान्यताएं अलग-अलग हैं। लेकिन हम सभी इंसान हैं, और हम सभी सम्मान के पात्र हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा महसूस न होने दें कि आप उतने अच्छे नहीं हैं। याद रखें कि आप सुंदर, मूल्यवान और प्यार के योग्य हैं।

दशहरा पर युवाओं को सरकार की सौगात, साल भर में मिलेंगे 66,000 रुपये; ऐसे करें आवेदन

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में युवाओं के हुनर को तराशने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का एलान किया था। इस स्कीम के तहत टाप 500 कंपनियों में अगले पांच साल में एक करोड़ युवाओं को कुशल करने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी मामले के मंत्रालय ने इस स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है।

नई दिल्ली। पढ़े-लिखे आर्थिक रूप से कमजोर युवा-युवतियों के लिए सरकार दशहरे पर सौगात लेकर आई है। दहशरे से पहले प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम की शुरुआत हो गई है। इस स्कीम में आवेदन के लिए सिर्फ वही युवा-युवती योग्य पात्र होंगे, जिनके परिवार की आय सालाना आठ लाख रुपए से कम है।

केंद्र सरकार का आरक्षण नियम भी इस स्कीम में लागू होगा। यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को आरक्षण मिलेगा लेकिन सिर्फ वही योग्य होंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे।

क्या है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम

इंटर्नशिप स्कीम की घोषणा इस साल बजट में की गई थी जिसके तहत टाप 500 कंपनियों में अगले पांच साल में एक करोड़ युवाओं को कुशल करने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी मामले के मंत्रालय ने इस स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है।

इसके तहत चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख युवाओं को रोजगार के लायक बनाने के लिए प्रशिक्षण व कुशलता हासिल करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण और कौशल विकास की अवधि 12 महीने की होगी और इस अवधि में उन्हें 5000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी।

4500 रुपए प्रतिमाह केंद्र सरकार देगी और कंपनी 500 रुपए उन्हें अपने सामाजिक दायित्व फंड से देगी। इसके अलावा कंपनी मामले मंत्रालय की तरफ से 6000 रुपए की एकमुश्त राशि भी सभी चयनित उम्मीदवारों को दी जाएगी।

यानी कि प्रशिक्षण हासिल करने वाले उम्मीदवारों को एक साल में 66 हजार रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। सभी राशि सीधे तौर पर उम्मीदवारों के खाते में दिए जाएंगे। इस इंटर्नशिप स्कीम से चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार पर 800 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।

वित्त एवं कंपनी मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह पूरी तरह से इंटर्नशिप कार्यक्रम है। कोशिश यह होगी कि चयनित उम्मीदवारों को उनके अपने जिले या आसपास के जिले में ही प्रशिक्षण का मौका दिया जाए। इस पूरे कार्यक्रम को चलाने के लिए कंपनी मामले के मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया है और pminternship.mca.gov.in पर जाकर हर कोई उस पोर्टल तक पहुंच सकता है।

कैसे करेंगे आवेदन

सीतारमण ने बताया कि तीन अक्टूबर से यह पोर्टल कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। आगामी 10 अक्टूबर तक कारपोरेट कंपनियां पोर्टल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अपनी पेशकश करेंगी। 12 अक्टूबर यानी कि दशहरे वाले दिन से लेकर 25 अक्टूबर तक इच्छुक योग्य उम्मीदवार प्रशिक्षण हासिल करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

26 अक्टूबर को कंपनी मामले का विभाग पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा जिसे कंपनियों के पास भेजा जाएगा। 27 अक्टूबर से सात नवंबर तक कंपनियां अपनी जरूरत के मुताबिक उम्मीदवारों का चयन करेंगी और उम्मीदवारों को इसकी सूचना दी जाएगी। 8-15 नवंबर के बीच उम्मीदवार कंपनियों की पेशकश को स्वीकार सकेंगे और आगामी दो दिसंबर से उनका इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।

कंपनी मामले के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि 111 कॉरपोरेट कंपनियां अब तक अपने यहां इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए तैयार हो गई है। इनमें महिंद्रा एंड महिंद्रा और मैक्स लाइफ जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। ज्यादा कंपनियां कृषि व इससे संबंधित सेक्टर के साथ ऑटोमोबाइल्स और फार्मा सेक्टर से जुड़ी हैं।

इंटर्नशिप स्कीम की पात्रता

दसवीं या बारहवीं पास आईटीआई सर्टिफिकेट धारक, पॉलिटेक्निक संस्था से डिप्लोमाधारी, या बीए, बीएससी, बी.काम, बीसीए, बीबीए, बी. फार्मा के डिग्रीधारक इस इंटर्नशिप स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं।

वहीं, आईआईटी, आईआईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आईआईएसईआर और ट्रिपल आईआईटी, सीए, सीएस, बीडीएस, एमबीबीएस की डिग्री रखने वाले या फिर पहले से किसी सरकारी इंटर्नशिप कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे छात्र पीएम इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं होंगे।

अगर माता-पिता में से कोई भी सरकार में स्थायी या नियमित कर्मचारी हैं तो वैसे बच्चे भी इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

अब स्टील कंपनियों के शेयरों में आएगी तेजी? चीन से इंपोर्ट घटाने की तैयारी में सरकार

परिवहन विशेष न्यूज

चीन स्टील बाजार का सबसे दिग्गज खिलाड़ी है। लेकिन वहां 2020 से डिमांड कमजोर है। चीन में प्रॉपर्टी संकट बढ़ने से चीजें और भी ज्यादा खराब हो गई। इससे स्टील का भाव कई साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। ऐसे में अपने स्टील को सस्ते भाव में भारत जैसे देशों में डंप करने लगा। चीन में स्टील की डिमांड लंबे वक्त तक कमजोर बनी रहने वाली हैं।

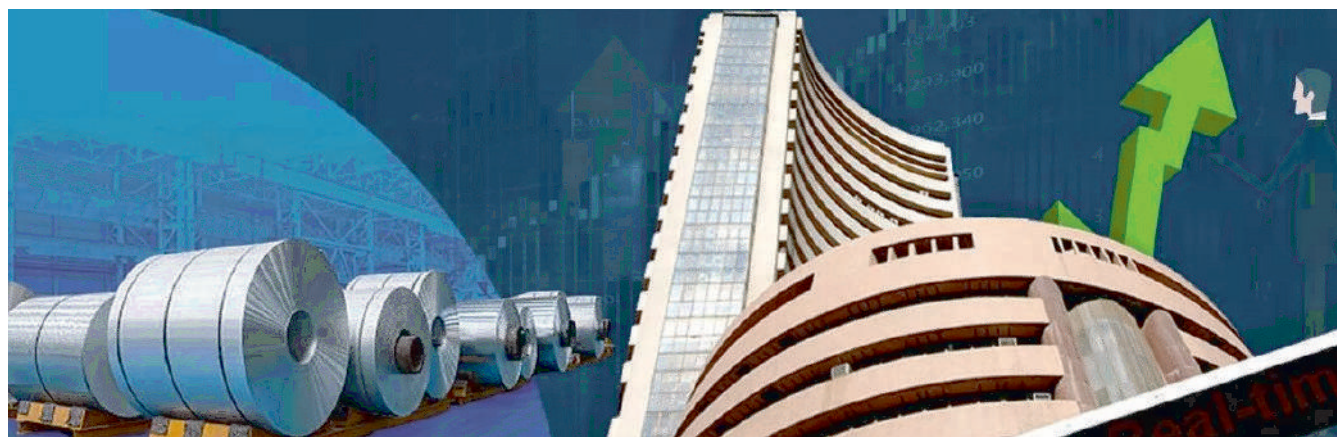

नई दिल्ली। भारत की स्टील कंपनियां काफी बुरे दौर से गुजर रही हैं। चीन लगातार सस्ता स्टील भारत में डंप कर रहा है। इससे घरेलू स्टील कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है और उनके मुनाफे पर भी दबाव बन रहा है। हालांकि, अब भारतीय स्टील कंपनियों को राहत मिल सकती है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी का कहना है कि सरकार चीन से स्टील डंपिंग रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। इससे संकेत मिलता है कि सरकार स्टील पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है।

चीन से भारत में होने वाली स्टील डंपिंग घरेलू इंडस्ट्री के लिए काफी चिंताजनक है। सरकार घरेलू स्टील इंडस्ट्री के हित में जरूरी कदम उठाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और वित्त मंत्रालय से भी बातचीत की जाएगी। हम चीन से स्टील आयात पर शुल्क 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 10-12 फीसदी करने का प्रस्ताव रखेंगे।

चीन सस्ता स्टील क्यों बेच रहा?

चीन स्टील बाजार का सबसे दिग्गज खिलाड़ी है। लेकिन, वहां 2020 से डिमांड कमजोर है। चीन में प्रॉपर्टी संकट बढ़ने से चीजें और भी ज्यादा खराब हो गई। इससे स्टील का भाव कई साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। ऐसे में अपने स्टील को सस्ते भाव में भारत जैसे देशों में डंप करने लगा। चीन की बड़ी स्टील कंपनियों का मानना है कि वहां स्टील की डिमांड लंबे वक्त तक कमजोर बनी रहने वाली हैं। भारत के स्टील निर्माता लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि चीन की स्टील डंपिंग पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि इससे घरेलू उद्योग बर्बाद हो रहा है।

स्टील फर्मों के शेयरों का हाल?

स्टील कंपनियों के शेयरों में लंबे वक्त से सुस्ती बनी हुई है। JSW स्टील और टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनियों ने पिछले एक साल में करीब 15 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, उषा मार्टिन लिमिटेड से निवेशकों को एक साल में 2 फीसदी का घाटा हुआ है। स्टील कंपनियों का यह हाल बुल मार्केट के दौर में है, जब अधिकतर सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है।

भारत में फूड पार्क बनाएगा यूएई, किसानों की आय बढ़ाने में मिलेगी मदद

भारत निवेश प्रोत्साहन के लिए यूएई में दफ्तर खोलने जा रहा है। यूएई दफ्तर खोलने के लिए मुफ्त में जमीन मुहैया करा रहा है। दुनिया के दस प्रमुख देशों में भारत का निवेश प्रोत्साहन दफ्तर खोलने का प्लान है। पिछले महीने 22 तारीख को सिंगापुर में ऐसा पहला दफ्तर खोला गया। निजी व सरकारी सहभागिता से खोले जाने वाले इस दफ्तर का काम निवेशकों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराना होगा।

मुंबई। यूएई भारत में दो अरब डॉलर के निवेश से फूड पार्क की स्थापना करने जा रहा है। फूड पार्क में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी। इससे भारतीय कृषि संबंधी वस्तुओं का निर्यात बढ़ेगा और किसानों को फायदा होगा। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी और कहा कि यूएई भारत में फूड पार्क लगाकर अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है।

अभी मध्य पूर्व से लेकर पश्चिमी दुनिया खाद्य आपूर्ति की चुनौती से जूझ रहा है। गुजरात के अहमदाबाद के पास फूड पार्क या फूड कोरिडोर के लिए जमीन की पहचान का काम शुरू हो गया है। पार्क में लगने वाली फूड प्रोसेसिंग यूनिट में इजरायल व अमेरिका की टेक्नोलाजी का इस्तेमाल किया जाएगा। निवेश पर भारत-यूएई के उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक के बाद मंगलवार को गोयल ने बताया कि अगले दो-ढाई साल में फूड पार्क के निर्माण को लेकर यूएई की तरफ से निवेश का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत के एमएसएमई के निर्यात को बढ़ाने के लिए यूएई में भारत मार्ट खोला जा रहा है और इसके निर्माण का काम वर्ष 2026 तक पूरा हो जाएगा।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा....

बीते अगस्त महीने में जारी हुए आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। इस भंडार में एक प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 3.609 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 591.569 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी इकाइयों की सराहना या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है।

मुंबई। आरबीआई ने बीती 16 अगस्त को भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े जारी किए थे। इसके अनुसार, यह भंडार 4.546 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 674.664 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 670.119 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया था। 2 अगस्त को समग्र भंडार 674.919 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। आंकड़ों के अनुसार, 16 अगस्त को समाप्त सप्ताह में, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, जो भंडार का एक प्रमुख घटक है, 3.609 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 591.569 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गईं। डॉलर के संदर्भ में व्यक्त विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी इकाइयों की सराहना या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। आरबीआई ने कहा कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 865 मिलियन डॉलर बढ़कर 60.104 बिलियन डॉलर हो गया। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 60 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.341 बिलियन डॉलर हो गए। सप्ताह के दौरान आईएमएफ के साथ भारत की आरक्षित स्थिति 12 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.65 बिलियन डॉलर हो गई।

विदेशी निवेशकों ने तीन सत्रों में 27 हजार करोड़ के शेयर बेचे, इजरायल-ईरान संघर्ष और चीनी बाजारों के बेहतर प्रदर्शन का दिख रहा असर

परिवहन विशेष न्यूज

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) अक्टूबर के सिर्फ तीन कारोबारी सत्रों में ही भारतीय बाजारों से 27142 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री कर चुके है। बीएसई में सूचीबद्ध शीर्ष-10 में से नौ कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 4.74 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है। इस सप्ताह केवल दो कंपनियों के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। इस आर्टिकल में विस्तार से जानें

नई दिल्ली। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और चीन के बाजारों के बेहतर प्रदर्शन का भारतीय शेयर बाजारों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इन कारणों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) अक्टूबर के सिर्फ तीन कारोबारी सत्रों में ही भारतीय बाजारों से 27,142 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री कर चुके है।

इससे पहले सितंबर में एफपीआई ने 57,724 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे, जो 2024 में किसी एक महीने में सबसे ज्यादा एफपीआई निवेश था। नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के डाटा के अनुसार, अप्रैल-मई के दौरान 34,252 करोड़ रुपये की निकासी के बाद जून से एफपीआई इक्विटी बाजारों में लगातार खरीदारी कर रहे थे।

इसके कारण 2024 में अब तक एफपीआई शुद्ध खरीदार बने हुए थे। सितंबर के अंत में एफपीआई का पूरे वर्ष में शुद्ध निवेश एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया था। लेकिन हालिया निकासी के बाद इक्विटी बाजारों में एफपीआई निवेश घटकर 73 हजार करोड़ रुपये के करीब रह गया है।

इक्विटी के अलावा, अक्टूबर के तीन कारोबार सत्रों में एफपीआई ने डेट या बांड बाजारों से 900 करोड़ रुपये की निकासी की है। हालांकि, डेट बाजारों में एफपीआई का कुल निवेश 2024 में अब तक एक लाख करोड़ रुपये के पार बना हुआ है।

खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार; गेहूं-चावल से भरा देश का भंडार, दलहन-तिलहन में गिरावट

वर्ष 2023-24 में चावल उत्पादन रिकार्ड 13.78 करोड़ टन पर पहुंच गया जो 2022-23 में 13.57 करोड़ टन था। गेहूं का उत्पादन भी 2022-23 के 11.05 करोड़ टन की तुलना में बढ़कर 11.32 करोड़ टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि दलहन उत्पादन 2.60 करोड़ टन से घटकर 2.42 करोड़ टन और तिलहन उत्पादन 4.13 करोड़ टन से घटकर 3.96 करोड़ टन रह गया।

नई दिल्ली। भारत का खाद्यान्न उत्पादन फसल वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 33.22 करोड़ टन पर पहुंच गया है। गेहूं और चावल की बंपर फसल की वजह से कुल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है। कृषि मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि फसल वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान इससे पिछले वर्ष के 32.96 करोड़ टन से 26.1 लाख टन की वृद्धि दर्शाता है।

इस दौरान चावल उत्पादन रिकार्ड 13.78 करोड़ टन पर पहुंच गया, जो 2022-23 में 13.57 करोड़ टन था। गेहूं का उत्पादन भी 2022-23 के 11.05 करोड़ टन की तुलना में बढ़कर 11.32 करोड़ टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, दलहन उत्पादन 2.60 करोड़ टन से घटकर 2.42 करोड़ टन रह गया और तिलहन उत्पादन 4.13 करोड़ टन से घटकर 3.96 करोड़ टन रह गया।

मंत्रालय ने दालों, मोटे अनाजों, सोयाबीन और कपास के उत्पादन में गिरावट का कारण 'महाराष्ट्र सहित दक्षिणी राज्यों में सूखे की स्थिति' को बताया है। गन्ने का उत्पादन 49.05 करोड़ टन से घटकर 45.31 करोड़ टन रह गया, तथा कपास का उत्पादन 3.36 करोड़ गांठ से घटकर 3.25 करोड़ गांठ (एक गांठ 170 किलोग्राम) रह गया।

भारत में खाद्यान्न में चावल, गेहूं, मोटे अनाज, बाजरा और दालों को शामिल किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि ये अनुमान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिली जानकारी पर आधारित हैं।

इस सीजन में धान की काफी अच्छी रोपाई हुई है। मानसून की बारिश ने इस बार धान की अच्छी रोपाई कराई है। सामान्य से अधिक बारिश एवं बुआई के रकबा से माना जा रहा है कि इस बार भी चावल का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर जा सकता है। भारत में 75 प्रतिशत धान का उत्पादन खरीफ मौसम (जून-सितंबर) में होता है।

चावल उत्पादन का टूटेगा रिकॉर्ड! क्या निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाएगी सरकार?

नई दिल्ली। मानसून की बारिश ने इस बार धान की अच्छी बुआई कराई है। अभी तक पिछले वर्ष की तुलना में 16.24 लाख हेक्टेयर में अधिक धान की रोपाई हो चुकी है। सामान्य से अधिक वर्षा एवं बुआई के रकबा से माना जा रहा है कि चावल का उत्पादन रिकार्ड स्तर पर जा सकता है।

केंद्र सरकार का अनुमान लगभग 13.80 करोड़ टन चावल उत्पादन का है, जो पिछली बार से करीब 13 लाख टन अधिक है। पिछले वर्ष चावल का उत्पादन 13.67 करोड़ टन था, जो 2022-23 के 1357.55 लाख टन की तुलना में 9.45 लाख टन अधिक था।

सामाजिक दायित्व के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए अगस्त 2022 से ही चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बासमती चावल के निर्यात पर भी अतिरिक्त शुल्क लगा दिया गया है। लेकिन, इस बार बेहतर उत्पादन को देखते हुए उम्मीद है कि निर्यात पर से प्रतिबंध हट सकता है।

भारत में 75 प्रतिशत धान का उत्पादन खरीफ मौसम (जून-सितंबर) में होता है। पिछले तीन वर्षों से दक्षिण-पश्चिमी मानसून पर अलनीनो का व्यापक असर देखा जा रहा था। इसके चलते देश में औसत से कम बारिश हो रही थी। कई हिस्से को सूखे का भी सामना करना पड़ रहा था। इसके चलते खरीफ फसलों की बुआई और रोपाई बुरी तरह प्रभावित हो रही थी।

इस बार अच्छी मानसूनी बारिश ने असिंचित क्षेत्र के एक बड़े हिस्से में भी बुआई को काफी हद तक आसान बना दिया है, जो देश की कुल कृषि भूमि का लगभग 50 प्रतिशत है। इस बार ला-नीना के चलते वर्षा ने रफ्तार पकड़ी है तो खरीफ फसलों की बुआई-रोपाई में भी गति आई है। अभी तक 1065.08 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई-रोपाई हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.23 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। इसमें भी सबसे ज्यादा चावल के रकबे में वृद्धि देखी जा रही है।

त्योहार पर मिलावटी मिठाइयों से कैसे सुरक्षित रहें, इसके लिए कुछ उपयोगी टिप्स

विजय गर्ग

त्योहार का समय उत्सव और खुशी का समय होता है लेकिन अगर आप इस दिवाली घर में गलत खाद्य पदार्थ लाते हैं तो कुछ भी गलत हो सकता है। कभी-कभी एफबीओ विनियामक प्रावधानों से अनभिज्ञ होते हैं, श्रमिकों में प्रशिक्षण की कमी होती है और कभी-कभी लाभ मार्जिन बढ़ाने के लिए जानबूझकर की जाने वाली मिलावट खाद्य पदार्थों को हानिकारक बना सकती है। अगर आप घर पर दिवाली के व्यंजन पकाते हैं तो भी मिलावटी कच्चे माल के कारण आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए कच्चा माल खरीदते समय, सुनिश्चित करें कि वे किसी विश्वसनीय विक्रेता से खरीदे जाएं जिसके पास FSSAI लाइसेंस हो। मिठाइयां, सूखे मेवे, चॉकलेट, कुकीज, जूस, स्नैक फूड आदि खरीदने से पहले पैकेजिंग पर एफएसएसएआई लोगो और लाइसेंस नंबर, 'सबसे अच्छा पहले/समाप्ति तिथि, बैच/लॉट नंबर, सामग्री की सूची, पोषण संबंधी लेबल की जांच करें। जानकारी जो कुछ चीजें हैं जो आपको सही खाद्य पदार्थ चुनने में मदद करती हैं। खाद्य निर्माताओं के लिए एक प्रमुख पहलू उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है। खाद्य पदार्थों में मिलावट को नियंत्रित करने और रोकने के लिए एफबीओ को सावधान रहने की जरूरत है कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला परिसर की सफाई, प्रसंस्करण के दौरान उपयोग किए जाने वाले उपकरण भोजन संभालने वाले श्रमिकों की व्यक्तिगत स्वच्छता अनुमत खाद्य योजकों, रंगों और सामग्रियों का सही उपयोग खाद्य ग्रेड पैकेजिंग सामग्री कच्चे माल, खाद्य उत्पादों और पानी का नियमित परीक्षण मिठाइयाँ कड़वा स्वाद छोड़ सकती हैं चूंकि त्योहारों के दौरान मिठाइयां सबसे अधिक मांग वाली खाद्य वस्तु होती हैं, इसलिए बेईमान मिलावटखोर जानबूझकर ऐसे पदार्थ मिला सकते हैं जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। मिठाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कुछ सामग्री हैं खोया, वर्क, घी, तेल, दूध, कृत्रिम स्वाद और रंग। इन सभी वस्तुओं में जानबूझकर आर्थिक लाभ के लिए मिलावट की जा सकती है। दूध में पानी जैसी हानिरहित चीज़ हो सकती है लेकिन इसमें चाक, यूरिया, साबुन और रासायनिक व्हाइटनर भी हो सकते हैं। खोया में कागज और स्टार्च हो सकता है. रसगुल्ले जो चने से बनाये जाते हैं जो मिलावटी दूध से भी आ सकते हैं। वर्क एल्यूमीनियम का हो सकता है, शुद्ध चांदी का नहीं। घी में वनस्पति या पशु वसा भी हो सकती है। यह जांचने के लिए कि दूध मिलावटी है या नहीं, चिकनी तिरछी सतह पर कुछ बूंदें डालें, यदि यह सफेद निशान छोड़ता है तो यह मिलावटी नहीं है और यदि यह तुरंत नीचे फिसल जाता है तो इसमें पानी है। एक बोतल में थोड़ा सा दूध डालें, उसका ढक्कन लगाएं, उसे हिलाएं, अगर उसमें झाग आ जाए तो उसमें साबुन है। - दूध में एक चम्मच सोया पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें, मिश्रण में लिटमस पेपर डुबा लें. यदि यह लाल या नीला हो जाए तो इसे फेंक दें क्योंकि इसमें यूरिया हो सकता है। घी और वनस्पति का परीक्षण करने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं और अगर वे गहरे लाल रंग के हो जाएं तो इसका मतलब है कि वे मिलावटी हैं। अपनी उंगलियों के बीच थोड़ा सा वर्क रगड़ें, अगर यह टूट जाए तो शुद्ध है और अगर गेंद बन जाए तो मिलावटी है। चमकीले रंग और सजी-धजी मिठाइयाँ खरीदने से बचें क्योंकि इनमें गैर-अनुमति कृत्रिम रंग हो सकते हैं। क्या चॉकलेट बेहतर हैं? उपहार देने की वस्तु के रूप में चॉकलेट को मिठाइयों पर प्राथमिकता दी गई है और यदि चॉकलेट ब्रांडेड नहीं हैं तो उनमें भारी धातुओं की मिलावट हो सकती है क्योंकि वे कोको से बने होते हैं जिनमें तांबा और सीसा हो सकता है। चॉकलेट में स्टार्च या लार्ड भी हो सकता है। एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 में भारी धातुओं का अधिकतम अनुमत स्तर तय किया है। हालांकि कुछ बेईमान व्यवसायियों द्वारा चॉकलेट को जानबूझकर दूषित भी किया जाता है। निम्न गुणवत्ता वाली चीनी का प्रयोग करें कोको में स्टार्च मिलाएं वजन बढ़ाने के लिए खनिज पदार्थ मिलायें गैर-अनुमत कृत्रिम रंग का प्रयोग करें टालनाऐसी चॉकलेट खरीदना जो ब्रांडेड नहीं हैं या किसी अज्ञात निर्माता की हैं, भले ही खुदरा विक्रेता कहता हो कि वे असली चॉकलेट हैं। कुछ निर्माता ब्रांडेड कंपनियों की चॉकलेट की नकल करते हैं और उन्हें असली चॉकलेट के रूप में पेश करते हैं। चॉकलेट में पानी मिलाकर स्टार्च की मिलावट की जांच की जा सकती है। यदि चॉकलेट दानेदार हो जाए और टूट जाए तो यह घटिया है। जूस प्राकृतिक नहीं हो सकते हाल के वर्षों में, पैकेज्ड जूस उपहार देने वाली वस्तुओं के रूप में लोकप्रिय हो गए हैं, लेकिन यह संभव है कि सभी जूस न तो 'प्राकृतिक' हों और न ही 'शुद्ध'। आपको लेबल ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि केवल वे जूस जो 100% प्राकृतिक हैं उनमें कोई अतिरिक्त चीनी नहीं होगी। संतरे के रस में रंगीन योजक हो सकते हैं जिनकी खाद्य नियमों के तहत अनुमति नहीं है। सेब का रस खराब सेब से बनाया जा सकता है और इसमें विषाक्त फंगल मेटाबोलाइट हो सकता है जो मतली और उल्टी का कारण बन सकता है। जूस को अधिक 'पीने योग्य' बनाने के लिए इसमें गाढ़ा करने वाले पदार्थ, इमल्सीफायर, एडिटिव्स और अतिरिक्त स्वाद भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि सभी फलों के जूस का स्वाद संभवतः हर बैच में एक जैसा नहीं हो सकता है। जूस में कीटनाशकों और कवकनाशी के अवशेष हो सकते हैं क्योंकि इनका उपयोग फलों की फसलों पर बड़े पैमाने पर किया जाता है और इसलिए प्रयोगशालाओं में परीक्षण की आवश्यकता होती है। आपके पास उच्च फ्रुक्टोज, कॉर्न सिरप या चीनी सिरप, चुकंदर चीनी कृत्रिम या प्रकृति के समान स्वाद, पोटेशियम सल्फेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, एस्कॉर्बिक एसिड इत्यादि भी हो सकते हैं। हमेशा लेबल पढ़ें ताकि आप सटीक सामग्री जान सकें क्योंकि फल रेपेय पदार्थरे कभी-कभी गलती से लेबल किए जाते हैं रे जूसरे में वास्तव में फलों की मात्रा बहुत कम हो सकती है। क्या सूखे मेवे रंगीन हैं? मिठाइयाँ सूखे मेवों से पिछड़ रही हैं और मांग में वृद्धि के कारण इस स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भोजन में मिलावट हो रही है। चूँकि आकार उन कारकों में से एक है जो सूखे खाद्य पदार्थों की कीमत तय करता है, मिलावटखोर सूखे फलों को एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड जैसे एसिड में भिगोते हैं जो आकार को बढ़ाते हैं, नट्स को चमकदार बनाते हैं और एक संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। पिस्ता सबसे अधिक मिलावटी सूखे फलों में से एक है क्योंकि इसे हरे रंग में रंगी हुई मूंगफली के साथ मिलाया जाता है। किशमिश में कृत्रिम रंग भी हो सकते हैं। कृत्रिम रंग मैलाकाइट हरा हो सकता है जिसे खाद्य पदार्थों में उपयोग की अनुमति नहीं है। गैर-अनुमत रंग एजेंटों से सिरदर्द, उल्टी हो सकती है और यहां तक कि गर्भवती महिलाओं में अजन्मे भ्रूण पर भी असर पड़ सकता है। छिलके वाले पिस्ते खरीदें, छिलके वाले नहीं। रंग का पता लगाने के लिए 100 मिलीलीटर उबलते पानी में एक मुट्ठी पिस्ता डालें, अगर पानी हरा हो जाता है तो इसका मतलब है कि यह मिलावटी है। किशमिश में रंग का पता लगाने के लिए 5 मिलीलीटर पानी में कुछ किशमिश डालें और इसमें 5 मिलीलीटर एचसीएल मिलाएं। अगर डिब्बे की ऊपरी परत में रंग दिखाई दे रहा है तो किशमिश मिलावटी है सूखे मेवों में एसिड का पता लगाने के लिए कुछ सूखे मेवे लें और उन पर पानी छिड़कें। छिड़के हुए पानी में लिटमस पेपर लगाएं यदि लिटमस पेपर का रंग बदल जाता है तो इसका मतलब है कि सूखे फलों में एसिड है। पैकेज्ड स्नैक फूड और कुकीज़ पैकेज्ड स्नैक फूड और कुकीज़ ने दिवाली पर मिठाइयों और चॉकलेट जैसे महंगे खाद्य पदार्थों की जगह ले ली है। हालाँकि, इन खाद्य उत्पादों में हाइड्रोजनीकृत वसा, संशोधित स्टार्च, स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थ, रंग और कई खाद्य योजक शामिल हो सकते हैं ताकि उत्पाद को स्वादिष्ट और आकर्षक बनाया जा सके। इन खाद्य पदार्थों का चयन करते समय उपयोग की जाने वाली सर्वोत्तम विधियों में से एक सामग्री सूची की जांच करना है। यदि उनमें उन सामग्रियों के नाम हैं जिनका आप आमतौर पर अपनी रसोई में उपयोग नहीं करते हैं तो आपको उनका उपयोग कम से कम करना चाहिए। इनमें फ्रुक्टोज सिरप, प्रोटीन आइसोलेट्स, बल्किंग एजेंट, थिकनर, इमल्सीफायर, कलरेंट और स्वाद बढ़ाने वाले तत्व शामिल हो सकते हैं।. इसके अलावा, इन खाद्य पदार्थों में नमक, चीनी और वसा की मात्रा अधिक होने की संभावना है जो स्वाद को बढ़ा देते हैं और शेल्फ जीवन को बढ़ा देते हैं लेकिन स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। यदि आप इन्हें छोटे विक्रेताओं से खरीदते हैं तो ये स्नैक फूड बार-बार इस्तेमाल किए जाने वाले सस्ते तेल में बनाए जा सकते हैं, जिससे ट्रांस वसा की मात्रा अधिक हो सकती है। बिस्कुट में हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल, परिष्कृत चीनी, परिष्कृत आटा या एडिटिव्स जैसे तत्व खाद्य पदार्थों का 'स्वस्थ' विकल्प नहीं हैं। यदि आप दुकानों और स्थानीय बेकरियों से मिठाई, नमकीन और कुकीज़ खरीदते हैं तो परिसर की सफाई और खाद्य संचालकों के स्वच्छता मानकों की जांच करना महत्वपूर्ण है।

ईडी के चार्जसीट से नाम हटाने को लेकर मोटी रकम की लेनी-देनी का मामला झारखंड में दर्ज

(कार्तिक कुमार परिच्छा)

सरायकेला: भ्रष्टाचार का गढ़ बना झारखंड में जमीन घोटाले मामले में आई ए एस अधिकारी से लेकर मंत्री तक लपेट में है । ऐसे में वहीं ईडी की चार्जशीट में नाम न आने को लेकर एक पक्ष द्वारा 70 लाख रुपये दिए जाने बाद में नाम नहीं हटने पर दोनो पक्षों की तरफ से एक चर्चित मामला रांची के पंडरा थाने में आज दर्ज की गयी है । मोटी रकम लेनी देनी देने के बावजूद ईडी की चार्जशीट में नाम आने के बाद मामला बिगड़ गया था और पैसे वापस मांगे जाने लगे। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। यहां तक अपहरण तक की बात कही गयी है ।

मिली जानकारी के अनुसार पैसे देने के बाद भी जब ईडी की चार्जशीट में नाम आया तो संजीव कुमार ने संजीत कुमार से पैसे वापस मांगे। जिस पर वकील ने पैसे न होने के एवज में 54 चेक काट कर दे दिए। साथ ही, अपनी गाड़ी भी पैसे के बदले दे दी और एक एग्रीमेंट बनाया। यह सारी घटना 2 अक्टूबर को हुई। उसके बाद 3 तारीख को वकील संजीत कुमार पंडरा थाने पहुंचे और उन्होंने संजीव कुमार और अन्य लोगों पर अपहरण और मारपीट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। उधर रांची के सीईओ का नाम हटाने में 7करोड रुपए वसूले जाने की भी खबर है। जिसका एक प्राथमिकी संजीव कुमार द्वारा दर्ज कराई गई है । मामला ईडी से जूडे होने एवं हाई लेवल होने के कारण पुलिस जांच में जुट गई है पर मिडिया को कुछ कहने से बच रही है । वैसे ईडी स्वयं जांच एजेन्सी है जिसे राज्यों रोकने हेतु कुछ राज्यों के सरकारें आवश्यक कदम उठाये थे पर उसकी जांच में धन की उगाही कैसे होती है देखना बड़ा दिलचस्प होगा ।

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में किसकी बनेगी सरकार? आज आएगा जनता का फैसला

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आएंगे। इन प्रदेशों में किसकी सरकार होगी... यह तस्वीर दोपहर तक साफ होने की उम्मीद है। हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर हैं। पिछले 10 वर्षों से प्रदेश की सत्ता पर भाजपा ही काबिज है। जम्मू और कश्मीर में लोगों का छह साल बाद सरकार का इंतजार खत्म होगा।

नई दिल्ली। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री का ताज पहनेगा इससे जुड़े सभी सवालों पर से मंगलवार को परदा हट जाएगा। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को घोषित हो जाएंगे। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के लोगों का पिछले छह सालों से सरकार को लेकर चला रहा इंतजार खत्म हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर में इससे पहले विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। इसके बाद वहां पीडीपी और भाजपा गठबंधन की सरकार बनी थी, हालांकि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पायी थी और समय से पहले गिर गई थी। बाद में नंबर 2018 में विधानसभा को भी भंग कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था।

निजी बस मालिक संघ आंदोलन से हटे, पश्चिम और दक्षिण ओडिशा में नहीं बंद की जाएंगी बस सेवाएं

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वर: पश्चिम और दक्षिण ओडिशा में बस सेवाएं बंद नहीं की जाएंगी। परिवहन मंत्री के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। वार्ता के बाद निजी बस मालिक संघ आंदोलन से हट गया है। 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान प्राइवेट बस ओनर्स एसोसिएशन ने किया था। यूनियन ने लक्ष्मी बस के खिलाफ बंद बुलाया था। यूनियन के सदस्यों ने चेतावनी दी कि 8 तारीख को शाम 6 बजे से 6 बजे तक 14 जिलों में निजी बसें नहीं चलनी चाहिए।जानकारी के मुताबिक, पिछली सरकार के लाइसेंस के तहत चलने वाली लशमी बस को अब मुख्यमंत्री बस सेवा का नाम दिया गया है और यह बस रिट्रीट से ब्लॉक मुख्यालय तक यात्रा करती थी। हालांकि, अब यूनियन ने अलग-अलग शहरों के लिए बस चलाने के फैसले का विरोध किया है। लक्ष्मी बस सेवा शुरू होने के बाद से ही निजी बस मालिक महासंघ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले कुछ समय से एपोस वार्ता के बाद बसें लंबे समय से चल रही हैं।

पश्चिम ओडिशा और दक्षिण ओडिशा निजी बस मालिक संघ दोनों ने मांग की है कि बसें चलाने का वर्तमान निर्णय किसी विदेशी राज्य को दिया जाना चाहिए और निजी बस मालिक संघ के साथ एक समझौता किया जाना चाहिए। वहीं, आज सुबह 9 बजे यूनियन प्रतिनिधियों की भारत के परिवहन मंत्री विभु भूषण जेना के साथ बैठक हुई। वार्ता के बाद निजी बस मालिक संघ आंदोलन से हट गया है।

प्रधानमंत्री ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की तबियत का लिया जायजा

कार्तिक कुमार परिच्छा

सरायकेला, अस्वस्थ चल रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह उनका हाल व तबियत के विषय में जानकारी ली । सनद रहे कि चंपाई सोरेन विगत दो दिनों से टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज रत थे ,आज डॉक्टरों ने उन्हें छुट्टी दे दी । पूर्व सी एम सह सरायकेला विधायक चंपाई सोरेन ने प्रधानमंत्री को अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि डॉक्टरों के अथक प्रयास और आम लोगों की दुआओं से अब वह पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं । पीएम ने चंपाई सोरेन की तारीफ करते हुए कहा कि आप अस्वस्थ रहने के बावजूद आस्पताल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आयोजित आदिवासियों के महासम्मेलन में शामिल हुए।

रेलवे कर्मचारियों को सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट, मिलेगा भारी बोनस

दिवाली से पहले 11 करोड़ रेलवे कर्मचारियों को बोनस का तोहफा मिल गया है। केंद्र सराकर ने 78 दिनों के बोनस को मंजूर कर दी है। इसका फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया है। भारतीय रेलवे के अच्छे प्रदर्शन के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को सुविधा देने के साथ ही कर्मचारियों का भी ख्याल रखता है। अब फेस्टिव सीजन के शुरुआत होती ही केंद्र सरकार ने करोड़ों रेलवे कर्मचारियों को खुशखबरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की कैबिनेट बैठक में रेलवे कर्मचारियों बोनस को मंजूरी मिल गई है। रेलवे कर्मचारियों के बोनस (Railways Employees Bonus) की जानकारी अश्विनी वैष्णव ने दी।

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने रेलवे कर्मियों के लिए बोनस को मंजूर कर दिया। कर्मचारी को टोटल 78 दिनों का बोनस देने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से कुल 11,72,240 कर्मचारियों को लाभ होगा। इनमें से अभी 58,642 कर्मचारियों का पदों पर भर्ती करने का प्रोसेस चल रहा है।

कर्मचारियों को कितना मिलेगा बोनस

भारतीय रेलवे की परफॉर्मेंस अच्छी रही, जिसके बाद कर्मियों को बोनस दिया जा रहा है। सरकार 2029 करोड़ रुपये का बोनस दे रही है। कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। इसका लाभ 11 करोड़ कर्मचारियों को होगा। रेलवे के प्रत्येक कर्मचारियों को मैक्सिमम 17,951 रुपये का बोनस मिलेगा।

इन कर्मचारियों को होगा लाभ

भारतीय रेलवे के सभी कैटेगरी के कर्मचारियों को बोनस का फायदा होगा। इसमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, ग्रुप सी स्टाफ, प्वाइंट्स मैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ आदि शमिल हैं।

बता दें कि भारतीय रेलवे हर साल दुर्गा पूजा/दशहरा त्योहारों से पहले प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) का एलान करता है। इस साल भी नवरात्र के पहले दिन रेलवे कर्मियों को बोनस देने का एलान किया गया है।

गहरा राज़

देखो राज़ है यह बहुत ही गहरा,
किसके सिर बंधे जीत का सेहरा!
अभी तो है प्रशासन का भी पहरा।
क्या? बीजेपी के प्रति भारी गुस्सा है,
इसके पीछे भी रणदीप और हुड्डा है?
सुना है कांग्रेस के प्रति एक लहर है,
क्या? मान ले सैनी इससे बेखबर है?
दलित समाज कांग्रेस से नाराज़ है,
देखो भाई यह भी एक गहरा राज़ है?
हाँ, अभी तो दो दिन का और पॉज़ है।
अभी सिर्फ लगाए जा रहे हैं कयास,
दीपेंद्र हुड्डा ने किए हैं बहुत प्रयास।
ज्योतिषी करे त्रिशंकु की संभावना है,
मिल-बाँटकर सत्ता पाने की भावना है।
अब तो हारने का सपना भी डरावना है,
क्योंकि वह चार दिन का ही पाहुना है?
रिजल्ट की राह देख रहे उम्मीदवार।
यह जनता ना कर दे कोई पलटवार।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इंदौर (मध्यप्रदेश)

साइबर क्राइम पर आधारित एपिसोड का पहला सीन आज़ छलेसर में फिल्माया

साइबर अपराधों से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बुलेट क्राइम टीवी चैनल के तहत बनाएं जा रहे एपिसोड : फ़िल्म निर्माता सावन चौहान

आगरा,संजय साग़र सिंह। डिजिटल अरेस्ट, स्पेम, स्कैम,समेत साइबर अपराध की अन्य धोखाधड़ी की घटनाओं को देखते हुए फ़िल्म निर्माता सावन चौहान ने साइबर अपराधों से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 'बुलेट क्राइम टीवी चैनल के तहत सायबर क्राइम पर आधारित पहले एपिसोड की शूटिंग आज़ छलेसर स्थित ओममान श्री ढाबा पर की गयी। इस सन्दर्भ में फ़िल्म निर्माता सावन चौहान ने कहा, देश-प्रदेशों और महानगरों में भी अब साइबर अपराध के खतरनाक मामले सामने आ रहे हैं। साइबर ठगी के ये मामले अब सिर्फ धमका कर डिजिटल अरेस्ट के जरिये लाखों-करोड़ों रुपये खाते में ट्रांसफर कराने तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि फोन पर मिली झूठी धमकी से डर कर बेकसूर लोगों की जान भी जाने लगी है। हाल ही में साइबर क्राइम की एक ऐसी हृदय विदारक एवं बेहद खतरनाक खबर आगरा से सामने आई जिसने हम सबको झकझोर दिया है। साइबर अपराधियों ने एक 58 वर्षीय शिक्षिका के पास +92 कोड से व्हाट्सऐप कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा था कि उनकी बेटी को सेक्स रैकेट के मामले में पकड़ा गया है। कॉलर की डीपी पर पुलिस की वर्दी पहने हुए किसी व्यक्ति की तस्वीर थी, जिसने महिला को पूरी तरह से गुमराह कर दिया और महिला से तुरंत एक लाख रुपये ट्रांसफर करने की मांग की और ऐसा न करने पर उनकी बेटी का वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी और बार-बार धमकाने के बाद शिक्षिका सदमे में आ आई, जिससे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ती चली गई और कुछ मिनटों बाद बेकसूर शिक्षिका की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गयी। साइबर अपराधियों के लालच ने एक खुशहाल परिवार तवाह कर दिया। समाज के लिए यह घटना बहुत ही दुःखद और चिंताजनक हैं। इस घटना ने साइबर अपराध की गंभीरता को उजागर कर दिया है। इस डिज़िटिल युग में साइबर अपराधों से लोगों को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है।

श्री चौहान ने आगे कहा, डिजिटल अरेस्ट, स्पेम, स्कैम समेत साइबर अपराध की अन्य घटनाओं को देखते हुए लोगों को साइबर अपराधों से जागरूक करने के उद्देश्य से हम बुलेट क्राइम टीवी चैनल के तहत सायबर क्राइम पर आधारित पहले एपिसोडों की शूटिंग कर रहे हैं। ये एपिसोड सन्डे के सन्डे चैनल पर दिखाएं जाएंगे। इन एपिसोडों की सूटिंग के दौरान इस विषय से संबंधित जानकार व्यक्तियों को भी फिल्माया जायेगा। साइबर सुरक्षा के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए सन्डे के सन्डे चैनल पर एपिसोड़ दिखाना एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इस एपिसोडो के माध्यम से हम साइबर सुरक्षा के बारे में जनता को जागरूक कर सकते है। सामाजिक जागरूकता के माध्यम से साइबर अपराध के खतरों और उनसे बचने के उपायों के बारे में बता सकते हैं। लोगों को विभिन्न ऑनलाइन स्कैम और धोखाधड़ी की जानकारी के बारे में जागरूक करना चाहिए ताकि वे सतर्क और सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि से बच सकें। साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने से ही लोग इंटरनेट और डिजिटल साधनों का सुरक्षित उपयोग कर सकेंगे और अपनी व्यक्तिगत जानकारी और पैसे को सुरक्षित रख पाएंगे। शूटिंग के दौरान डायरेक्टर दीपक सेन, एंकर दीपक शर्मा, आर्टिस्ट सुरेंद्र वर्मा, राकेश त्यागी, नितिन कुमार आदि टीम के सदस्य मौजूद रहे, विशेष सपोर्ट सुनील धाकरे का रहा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023